रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)—73 REGISTERED No. D.(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12, 1977/माघ 23, 1898
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12, 1977/MAGHA 23, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप म रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1977

का० आ० 465.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 24 की उपधारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री अशोक कुमार, मालिक मैसर्स अशोक इन्डस्ट्रीज, हैदराबाद तथा अन्यों के विरुद्ध मुकदमा आर० सी० नं० 13/ई०/70 मद्रास एवम् श्री विजय कुमार बलदावा, मालिक मैसर्स नरेन्द्र इन्डस्ट्रीज, हैदराबाद तथा अन्यों के विरुद्ध मुकदमा आर० सी० नं० 13/ई०/71-मद्रास में विचारण न्यायालय में अभियुक्तों के अभियोजन का संचालन करने हेतु श्री एस० जी० सामन्त अधिवक्ता बम्बई को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[सं० 225/68/76-ए०वी०डी०-(II)]

CABINET SECRETARIAT
(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 28th January, 1977

S.O. 465.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the Central Government hereby appoints Shri S. G. Samant, Advocate, Bombay as a Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of the accused in cases RC No. 13/E/70-Madras against Shri Ashok Kumar, Prop: M/s. Ashoka Industries, Hyderabad and others and RC No. 13/E/71-Madras against Shri Vijaya Kumar Baldawa, Prop: M/s. Narendra Industries, Hyderabad and others in the trial courts at Bombay.

[No. 225/68/76-AVD. (II)]

आदेश

का० आ० 466.—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित अपराधों के अन्वेषण करने के लिये दिल्ली विशेष स्थापना के सदस्यों की शक्तियों एवम् अधिकारिता का सिक्किम राज्य विस्तार करती है, अर्थात्:—

(क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धाराएं 120-बी, 124-ए, 161, 162, 163, 164, 165, 165-ए, 166, 167 168, 169, 171-ई०, 171-एफ, 182, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 211, 218, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263-ए, 379, 380, 381 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 403, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 465, 466, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477-ए, 489-ए, 489-बी, 489-सी, 489-डी, 489-ई, 500, 501, 502 तथा 505 के अधीन दण्डनीय अपराध।

(ख) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2) के अधीन दण्डनीय अपराध तथा

(ग) उपरोक्त खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में उल्लिखित अपराधों के सम्बन्ध में या उनसे सम्बन्धित प्रयत्न दुष्प्रेरणा और षड्यन्त्रों तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न हुई वैसी ही कार्रवाई के दौरान किया गया अन्य कोई अपराध ।

[सं० 228/7/76-ए० वी० डी० (II)]
एस० डी० गुप्ता, अवर सचिव

ORDER

S.O. 466.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 6, of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, with the consent of the Government of the State of Sikkim, hereby extends to the State of Sikkim the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment for the investigation of the offences specified below, namely :—

(a) Offences punishable under sections 120-B, 124-A, 161, 162, 163, 164, 165, 165A, 166, 167, 168, 169, 171E, 171F, 182, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 211, 218, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263A, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 403, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 465, 466, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477A, 489A, 489B, 489C, 489D, 489E, 500, 501, 502, and 505 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);

(b) Offences punishable under the Prevention of Corruption Act, 1947 (2 of 1947); and

(c) attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, the offences mentioned in clauses (a) and (b) above and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/7/76-AVD(II)]
S. D. GUPTA, Under Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1977

का० आ० 467.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के परामर्श से, श्री ओ०एस० चौहान के स्थान पर श्री डी०सी० मिश्र, आई० ए० एस०, मुख्य सचिव, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह प्रशासन, को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेशों तक अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/अ०नि० द्वी०/76]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 20th January, 1977

S.O. 467.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Andaman and Nicobar Island Admn., hereby nominates Shri D. C. Misra, Chief Secretary of Andaman and Nicobar Islands Administration, as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands with effect from the date he takes charge of the office and until further orders vice Shri O. S. Chauhan.

[No. 154/ANI/76]

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1977

का० आ० 468.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से, श्री पी० पी० श्रीवास्तव के स्थान पर श्री एच० एस० दुबे, आई०ए०एस०, वित्तीय आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/हि०प्र०/77]
प्र० कु० मिश्र, सचिव

New Delhi, the 21st January, 1977

S.O. 468.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Himachal Pradesh, hereby nominates Shri H. S. Dubay, I.A.S., Financial Commissioner, Himachal Pradesh as the Chief Electoral Officer with effect from the date he takes charges of the office and until further orders vice Shri P. P. Srivastava.

[No. 154/HP/77]
P. K. MISRA, Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th January, 1977

S.O. 469.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 4777 dated the 3rd December 1976, published in the Gazette of India part II, section 3, sub-section (ii), dated the 25th December 1976 at page 4489 for "Employees (Conditions of Services) Act, 1976" read "Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976".

[No. U-11030/6/76-UTL]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

का० आ० 470.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में निदेश करते हैं कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह भू-राजस्व और भूमि सुधार विनियम, 1966 (1966 का 2) के धारा 6 और धारा 46 के उप धारा (1) के अधीन सरकार के अधिकारों का प्रयोग भी करेंगे।

[सं०य० 11030/7/76-यू०टी०एल०]
हरीश चन्द्र बक्षी, अवर सचिव

New Delhi, the 29th January, 1977

S.O. 470.—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Chief Commissioner of the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers of the Government under section 6, and sub-section (1) of section 46 of the Andaman and Nicobar Islands Land Revenue and Land Reforms Regulation, 1966 (2 of 1966).

[No. U-11030/7/76-UTL]
H. C. BAKSHI, Under Secy

वित्त मंत्रालय

राजस्व और बैंकिंग विभाग

नई दिल्ली 9 नवम्बर, 1976

आय-कर

का० आ० 471.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखंण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सर्वश्री एफ० एस० मानावालन को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. अधिसूचना सं० 469 (404/138/73 आई०/टी० सी०/सी० तारीख 10-9-1973 द्वारा की गई श्री ए० सुन्दरम की नियुक्ति रद्द की जाती है।

3. यह अधिसूचना सर्वश्री एफ० एस० मानावालन के कर वसूली अधिकारियों के रूप में कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं० 1551 (फा० सं० 404/95/76-आई० टी०सी०सी०)]

एस० आर० वधवा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Banking)

New Delhi, the 9th November, 1976

INCOME-TAX

S.O. 471.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Sri F. S. Manavalan who is a Gezetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Sri A. Sundaram made under Notification No. 469 (404/138/73-ITCC) dated 10-9-1973 is hereby cancelled.

3. This Notification shall come into force with effect from the date Sri F. S. Manavalan takes over as Tax Recovery Officer.

[No. 1551 (F. No. 404/95/76-ITCC)]

S. R. WADHWA, Dy. Secy

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1976

आय-कर

का० आ० 472.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वी० के० अरोरा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2 अधिसूचना संख्या 466 (फा० सं० 404/130/73-आई०टी० सी० सी०) तारीख, 10 सितम्बर, 1976 के अधीन कर वसूली अधिकारी के रूप में की गई श्री आर० सी० निगम की नियुक्ति श्री वी० के० अरोरा के कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से रद्द की जाती है।

3 यह अधिसूचना श्री वी० के० अरोरा के कर वसूली अधिकारी के रूप मे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं० 1562 (फा०सं० 404/197/76-आई०टी०सी०सी)]

एच० वेन्कटरमन, उप सचिव

New Delhi, the 24th November, 1976

INCOME-TAX

S.O. 472.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri V. K. Arora who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri R. C. Nigam as Tax Recovery Officer made under Notification No. 466 (F. No 404/130/73-ITCC) dated 10th September, 1976 is hereby cancelled with effect from the date Shri V. K. Arora takes over as Tax Recovery Officer.

3. This Notification shall come into force with effect from the date Shri V. K. Arora takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 1562 (F. No. 404/197/76-ITCC)]

H. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1976

आय-कर

का० आ० 473—अधिसूचना सं० 558 तारीख 15 फरवरी, 1974 के अनुक्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1976 से 3 वर्ष की और अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् —

(i) यह कि उक्त संस्था छूट के अधीन प्राप्त निधियों का हिसाब पृथक से रखेगा।

(ii) यह कि ऐसी निधियों का उपयोग केवल समाज विज्ञान में अनुसंधान की प्रगति के लिए किया जाएगा, और

(iii) यह कि संस्था भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को, छूट के अधीन संगृहीत निधियों और वह रीति जिसमें उनका उपयोग किया गया है दर्शित करने वाली वार्षिक रिपोर्ट भेजेगी।

संस्था

किशोर भारती, बानखेड़ी जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश।

[सं० 1546 (फा० सं० 203/41/76-आई०टी०ए० II]

टी०पी० अग्रवालवाला, निदेशक

(Revenue Wing)

New Delhi, the 1st November, 1976

INCOME-TAX

S.O. 473.—In continuation of Notification No. 558 dated 15th February, 1974, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been

approved by the Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions for a further period of three years with effect from 1st April, 1976.

(i) That the Kishore Bharati shall maintain separate accounts of the funds collected by them under the exemption.

(ii) That such funds shall be utilised exclusively for promotion of research in Social Sciences; and

(iii) That the Institute shall send an Annual Report to the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, showing the funds collected under the exemption and the manner in which the funds were utilised.

INSTITUTION

Kishore Bharati, Bankheri, Dist. Hoshangabad, M.P.

[No. 1546 (F. No. 203/41/76-ITA. II)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Director

(बैंकिंग पक्ष)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1977

का० आ० 474.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 1 मार्च, 1976 से प्रारम्भ होकर 28 फरवरी, 1978 को समाप्त अवधि के लिए 'दि सेफ कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई, पर लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ० 8/11/76-ए०सी०]

(Banking Wing)

New Delhi, the 21st January, 1977

S.O. 474.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Safe Cooperative Bank Ltd., Bombay for the period from 1 March 1976 to 28 February 1978.

[No. F. 8/11/76-AC]

का० आ० 475.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 दिसम्बर, 1975 से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर 1977 को समाप्त अवधि के लिए 'दि उटकमंड टाउन कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि०, 'उटकमंड', पर लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ० 8/11/76-ए०सी०]

वी०एन० बहादुर, उपसचिव

S.O. 475.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Ootacamund Town Co-operative Urban Bank Ltd. Ootacamund for the period from 31 December, 1975 to 31 December 1977.

[No. F. 8/11/76-AC]

V. N. BAHADUR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1977

का० आ० 476.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री के०पी०ए० मेनन के स्थान पर राजस्व और बैंकिंग विभाग (बैंकिंग पक्ष), नयी दिल्ली के निदेशक श्री जे०सी० राय को एतद्द्वारा इलाहाबाद बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/6/76-बी०ओ० I]

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

New Delhi, the 24th January, 1977

S.O. 476.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri J. C. Roy, Director, Department of Revenue & Banking (Banking Wing), New Delhi as a Director of Allahabad Bank, vice Shri K. P. A. Menon.

[No. F. 9/6/76-BO. I]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

RESERVE BANK OF INDIA

(Central Office)

(Department of Accounts and Expenditure)

CORRIGENDUM

Bombay, the 25th January, 1977

S.O. 477.—In the statement of Affairs of the Reserve Bank of India Banking Department, for the week ended 3rd December 1976, published in the Part II Section 3 (ii) of the Gazette of India dated 1st January 1977, the following corrigendum may be noted on page 23 the figures Rs. 145,00,000 under the head 'National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund, may be read as Rs. 145,00,00,000.

[Reference Gen. No. 475/4-77/8]

Sd./-Illegible, p. Chief Accountant

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1976

आय-कर

का० आ० 478.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी अधिसूचना सं० 1240 (फा० सं० 187/11/75—आ० क० (ए 1) तारीख 21-2-76 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है,

क्रम सं० 83 के सामने स्तंभ (1) से (5) के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

क्रम सं०	व्यक्ति	आ०क०अ०	आ० क० स० कलक्टर	स० आ० अपील	आ० क० आ०
1	2	3	4	5	6
83.	ऐसे व्यक्ति जो भारत में अधिवासी नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति जो अपने प्रस्थान के समय भारत में अधिवासी होते हुए भी आयकर प्राधिकारी की राय में भारत में वापस नहीं आना चाहते और ऐसे व्यक्ति जो पहले भारत में कहीं भी निर्धारित नहीं किए गए हैं और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230(1) के अधीन विहित प्रमाणपत्र के लिए आयकर अधिकारी विदेश प्रभाग पुणे को आवेदन करते हैं।	आ० क० अ० विदेश प्रभाग, पुणे	आ० क० स० पुणे, रेंज-1, पुणे	स० आ० अपील पुणे, रेंज 1, पुणे	आ०क०आ० पुणे, 1, पुणे

[सं० 1576/फा० सं० 191/30/76-आई० टी० (ए I)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 9th December, 1976

INCOME-TAX

S.O. 478.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 1240 (F.No.187/11/75-IT (AI) dated 21-2-76.

The entries under columns 1 to 5 against S.No. 83 shall be substituted by the following:—

S. No.	Persons	I.T.O.	I.A.C.	A.A.C.	C.I.T.
1	2	3	4	5	6
83.	Persons not domiciled in India and persons who even if domiciles in India at the time of their departure have in the opinion of Income-tax authority no intention of returning to India and persons who are not previously assessed any where in India and who apply for the Certificate prescribed under section 230(1) of the I.T. Act, 1961, to the I.T.O. Foreign Section, Pune.	I.T.O. Foreign Section, Pune,	I.A.C. Pune, Range-I, Pune.	A.A.C. Pune, Range-I, Pune.	C.I.T. Pune-I, Pune.

[No. 1576/F.No. 191/30/76-IT(AI)

M. SHASTRI, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1977

का०आ० 479.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुएं निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन हों :

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) द्वारा अपेक्षित के अनुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है :

अतः अब उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1040, तारीख 30 मार्च, 1966 को अतिष्ठित करते हुए उक्त प्रस्तावों को उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की सम्भावना है,

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे तो वह उसे इस आदेश के राजपत्र

में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर', 14/1/बी एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल), कलकत्ता-700001 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि इस आदेश के उपाबन्ध 1 में विनिर्दिष्ट इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुएं निर्यात से पूर्व निरीक्षण के अधीन होंगी;

(2) इस आदेश के उपाबन्ध II में दिए गए इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो कि निर्यात से पूर्व ऐसी इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं पर लागू होगा;

(3) (क) भारतीय या अन्य किसी राष्ट्रीय मानक को, तथा

(ख) निर्यात-कर्ता द्वारा घोषित निर्यात संविदा के स्वीकृत विनिर्देशों को इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अन्तर्गत मान्य अभिकरणों में से किसी एक द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं का परेषण निरीक्षण संबंधी शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात योग्य है या उस पर उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य चिह्न या मुद्रा लगाई गई है।

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी खोजों को इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं के वास्तविक नमूनों के भू, वायु तथा समुद्र-मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी।

4. इस आदेश में इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं से उपाबन्ध 1 में दी गई वस्तुओं में से कोई भी अभिप्रेत है।

उपाबन्ध I

[पैरा 1 तथा 4 का उप-पैरा (1) देखिए]

1. संरचनात्मक इस्पात (मानक क्वालिटी)।
2. जस्तीकृत इस्पात की चद्दरें (सपाट तथा नलीदार)।
3. तार तथा टेलीफोन के प्रयोजन के लिए जस्तीकृत लोहे तथा इस्पात का तार।
4. नरम इस्पात का तार।
5. कंक्रीट प्रबलन के लिए नरम इस्पात तथा मध्यम तनन इस्पात छड़ें तथा कर्षित कठोर इस्पात का तार।
6. कार्बन इस्पात की शीत वेलित चद्दर।
7. उच्च तनन वाला इमारती इस्पात।
8. कार्बन इस्पात की तप्त वेलित चद्दरें तथा पत्तियां।
9. संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए कीलक छड़ें।
10. संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए उच्च तनन वाली कीलक छड़ें।
11. गढ़ने के लिए कार्बन इस्पात की छड़ें, बेलनाकार, ब्लूम, पट्टियां।
12. संरचनात्मक इस्पात (साधारण क्वालिटी)।
13. संरचनात्मक इस्पात (द्रवण वेल्डिंग क्वालिटी)।
14. सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए मशीन के पुर्जों के उत्पादन के लिए कार्बन इस्पात की छड़ें।
15. संरचनात्मक इस्पात में पुनः वेलित करने के लिए कार्बन इस्पात के बेलनाकार (मानक क्वालिटी)।
16. संरचनात्मक इस्पात में पुनः वेलित करने के लिए कार्बन इस्पात के बेलनाकार (साधारण क्वालिटी)।
17. तप्त वेलित इस्पात की पत्तियां (गांठ बांधने के लिए)।
18. कंक्रीट प्रबलन के लिए तप्त वेलित नरम इस्पात मध्यम तनन इस्पात तथा उत्पाद सामर्थ्य इस्पात की विरूपित छड़ें।
19. कंक्रीट प्रबलन के लिए शीत बंटी हुई इस्पात की छड़ें।
20. बॉयलरों के लिए इस्पात के कीलक तथा आड़ी छड़ें।
21. बॉयलरों के लिए इस्पात की प्लेटें।
22. धातु आर्क वेल्डिंग के लिए इलक्ट्रोड क्रोड तार के लिए नरम इस्पात।
23. इस्पात की चारखानेदार प्लेटें।
24. तप्त कार्य के लिए औजार तथा डाई इस्पात।
25. खराद और प्रेरण कठोरन इस्पात।
26. शीत कार्य के लिए औजार तथा डाई इस्पात।
27. आम अभियांत्रिक कार्यों के लिए मिश्र इस्पात के बेलनाकार ब्लूम तथा पट्टियां।
28. गोलियों तथा रोलरों के केज के शीत वेलित कार्बन इस्पात।
29. गोलियों, रोलरों और बेयरिंग रेसिज के लिए कार्बन-क्रोमियम इस्पात।
30. गढ़न इस्पात।
31. कार्बन तथा कार्बन-मैंगनीज बाधारहित काटने वाला इस्पात।
32. केस कठोरन इस्पात।
33. बेयरिंग उद्योग में प्रयोग के लिए कीलकों के लिए क्रोमो-कार्बन इस्पात का तार।
34. बेयरिंग उद्योग में प्रयोग के लिए कार्बनीय (कैबराइजिंग) इस्पात।
35. कठोरन और मृदुकरनीय इस्पात।
36. डाप फोर्जिंग के लिए डाई ब्लॉकों के लिए इस्पात।
37. बर्तनों तथा अस्पताल के बर्तनों के लिए स्टेनलेस स्टील की छड़ें, कुण्डलियां तथा गोल प्लेटें।

उपाबन्ध II

[पैरा 2 का उप-पैरा (2) देखिए]

[निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अन्तर्गत बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप]

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1977 है।

(2) ये को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत मान्य अभिकरणों में से कोई एक अभिप्रेत है;

(ग) इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं से उपबन्ध-1 में दी गई वस्तुओं में से कोई भी अभिप्रेत है।

3 निरीक्षण का आधार :—निर्यात की जाने वाली इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है।

4 निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात-कर्ता आने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में देगा और ऐसी सूचना के साथ अभिकरणों में से किसी एक को निर्यात संविदा में दिए गए विनिर्देशों की तकनीकी विशेषताओं का ब्यौरावार वर्णन करते हुए एक घोषणापत्र भी देगा ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्रत्येक सूचना तथा घोषणा पोत लदान की अनुसूचित तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले दी जाएगी। सूचना की एक प्रति उसी समय परिषद् के निरीक्षण के स्थान से निकटतम के कार्यालयों में से किसी एक को दी जाएगी, यथा :—

निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर', (आठवां मंजिल) 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-700001।

क्षेत्रीय कार्यालय :

1. निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'अमन चैम्बर्स' (पांचवीं मंजिल) 113, महर्षि कर्वे मार्ग, बम्बई-4

2. निर्यात निरीक्षण परिषद्, मनोहर बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, एर्नाकुलम, कोचीन-11

3. निर्यात निरीक्षण परिषद्, 13/37, पश्चिमी विस्तार क्षेत्र, आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-5

(3) उप-नियम (1) के अन्तर्गत सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं का नियम 3 तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार निरीक्षण करेगा।

(4) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् अभिकरण तुरन्त ही परेषण को यह सुनिश्चित करने के लिए इस ढंग से सील या स्टेंसिल करेगा कि सील या स्टेंसिल किए गए माल के साथ छेड़-छाड़ न की जा सके। अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यात-कर्ता चाहता है तो परेषण अभिकरण द्वारा सील/स्टेंसिल नहीं भी किया जाएगा। तथापि, ऐसी दशा में, निर्यात-कर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील कर सकने का हकदार नहीं होगा।

(5) यदि अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं का परेषण नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो वह निरीक्षण की समाप्ति के सात दिनों के भीतर निर्यात-कर्ता को यह घोषणा करते हुए कि परेषण निर्यात योग्य है, प्रमाण-पत्र देगा। प्रमाण-पत्र की एक प्रति उसी समय उप-नियम (2) में दिए गए परिषद् के निकटतम के कार्यालय को भेजी जाएगी :

परन्तु जहां अभिकरण का यह समाधान नहीं होता वहां वह उक्त सात दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर देगा तथा ऐसे इन्कार की सूचना, उसके कारणों सहित, निर्यात-कर्ता को देगा और परिषद् के निकटतम कार्यालय को पृष्ठांकित करेगा।

5. मान्य चिन्हों को लगाना और उसकी प्रक्रिया भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिह्न) अधिनियम, 1952 (1952 का 32) भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिह्न) नियम, 1955 तथा भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिह्न) विनियम, 1955 तथा इस संबंध में भारतीय मानक संस्थान द्वारा बनाई गई प्रक्रिया जहां तक हो सकती है, इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं के निरीक्षण पर जिसमें वे पूर्व लागू होंगी।

6. निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के प्रयोजन के लिए, इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुओं का निरीक्षण—

(क) विनिर्माता के परिसर पर, या

(ख) उस परिसर पर जहां इस्पात तथा इस्पात से बनी वस्तुएं निर्यात-कर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं परन्तु यह तब जब वहां इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त परख सुविधाएं हों, किया जाएगा।

7. निरीक्षण शुल्क :—निर्यात-कर्ता इन नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण फीस एक रुपया पचास पैसे (1.50) प्रति टन की दर से फीस के रूप में अभिकरण को देगा। यह फीस कम से कम एक सौ रुपये होगी।

8. अपील :—(1) नियम 4 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने के इन्कार से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इन्कार की सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सात से अन्यून और सात से अनधिक व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता का कम से कम दो-तिहाई गैर सरकारी सदस्य होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी।

[सं० 6(7)/76-नि०नि० तथा नि०उ०]

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 12th February, 1977

S.O. 479.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), steel and steel products should be subject to inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S. O. 1040 dated the 30th March, 1966, the Central Government hereby published the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2 Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within forty-five days of the date of publication of this order in the Gazette of India to the Export Inspection Council 'World Trade Centre', 14/1B Ezra Street (7th floor), Calcutta-700001.

PROPOSALS

(1) To notify that steel and steel products specified in Annexure I to this order shall be subject to inspection prior to export;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Steel and Steel Products (Inspection) Rules, 1976, set out in Annexure II to this order as the type of inspection which would be applied to such steel and steel products prior to export;

(3) To recognise—

(a) Indian or any other national standard, and

(b) the specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract as the standard specifications for steel and steel products;

(4) To prohibit the export in the course of international trade of such steel and steel products unless the same are accompanied by a certificate issued by any of the agencies recognised under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the consignment of steel and steel products conforms to the conditions relating to inspection and is exportworthy or affixed with a seal or a mark recognised by the Central Government under section 8 of the said Act.

3. Nothing in this order shall apply to the export by sea, land or air of bonafide samples of steel and steel products to prospective buyers.

4. In this order steel and steel products shall mean any of the items given in Annexure I.

ANNEXURE I

[See sub-paragraph (1) of paragraph 1 and paragraph 4]

1. Structural steel (standard quality)
2. Steel sheets, galvanised (plain and corrugated)
3. Iron and steel wire, galvanised for telegraph and telephone purposes
4. Mild steel wire
5. Mild steel and medium tensile steel, bars and hard-drawn steel wire for concrete reinforcement.
6. Carbon steel sheets, cold rolled
7. Structural steel, high tensile
8. Carbon steel sheet and strip hot rolled
9. Rivet bars for structural purposes
10. High tensile rivet bars for structural purposes
11. Carbon steel bars, billets, blooms and slabs for forgings
12. Structural steel (ordinary quality)
13. Structural steel (fusion welding quality)
14. Carbon steel bars for production of machine parts for general engineering purposes
15. Carbon steel billets for re-rolling into structural steel (standard quality)
16. Carbon steel billets for re-rolling into structural steel (ordinary quality)
17. Hot rolled steel strips (baling)
18. Hot rolled mild steel medium tensile steel and high yield strength steel deformed bars for concrete reinforcement
19. Cold-twisted steel bars for concrete reinforcement
20. Steel rivet and stay bars for boilers
21. Steel plates for boilers
22. Mild steel for metal arc welding electrode Core wire
23. Steel chequered plates
24. Tool and die steels for hot work
25. Tool and die steels for cold work
26. Flame and induction hardening steels
27. Alloy steel billets, blooms and slabs for forging for general engineering purposes
28. Cold-rolled carbon steel strips for ball and roller bearing cages.
29. Carbon-chromium steel for the manufacture of balls, rollers and bearing races
30. Mould steels
31. Carbon and carbon-manganese free-cutting steels
32. Case hardening steels
33. Low-carbon steel wire for rivets for use in bearing industry
34. Carburising steels for use in bearing industry
35. Steels for hardening and tempering
36. Steel for die blocks for drop forgings
37. Stainless steel sheets, coils and circles for utensils and hospital ware.

ANNEXURE II

[See sub-paragraph (2) of paragraph 2]

[Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963]

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the export of Steel and Steel Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1977, and

(2) They shall come into force on.....

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) 'Agency' means any of the agencies recognised under section 7 of the Act.

(c) 'Steel and steel products' mean any of the items given in Annexure I.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Steel and steel products for export shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. Procedure of inspection.—(1) Any exporter intending to export steel and steel products shall give intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation a declaration of the specifications stipulated in the export contract giving details of all the technical characetristics to any one of the agencies to enable it to carry out inspection in accordance with rule 3.

(2) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall be given not less than two weeks before the scheduled date of shipment. A copy of the intimation shall simultaneously be endorsed to any of the following offices of the Council, which is nearest to the place of inspection, namely :—

Regional Offices :

Export Inspection Council
'World Trade Centre' (7th floor)
14/1B Ezra Sreet,
Calcutta-700001.

1. Export Inspection Council
'Aman Chambers' (4th floor)
113 Maharashi Karve Road,
Bombay-4.

2. Export Inspection Council
Manohar Buildings
Mahatma Gandhi Road,
Ernakulam, Cochin-11.

3. Export Inspection Council
13/37 Western Extension Area,
Arya Samaj Road,
Karol Bagh,
New Delhi-5.

(3) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1), the Agency shall carry out the inspection of steel and steel products in accordance with rule 3 and the instructions, if any, issued by the Council in this regard.

(4) After completion of inspection, the Agency shall immediately seal or stencil the consignment in a manner so as to ensure that the sealed or stencilled goods cannot be tampered with. In case of rejection, if the exporter so desires the consignment may not be sealed/stencilled by the Agency. In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

(5) When the Agency is satisfied that the consignment of steel and steel products complies with the requirements of rule 3, it shall within seven days of completion of inspection issue a certificate to the exporter declaring that the consignment is exportworthy. A copy of the certificate shall simultaneously be sent to the nearest office of the Council as given in sub-rule (2).

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days refuse to ir the such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor, and endorse a copy to he nearest office of he Council.

5. Affixation of recognised mark and procedure thereof.—The provisions of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act 1952 (32 of 1952), the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, and the procedure laid down by the Indian Standards Institution in this behalf shall, so far as may be apply to the inspection of steel and steel products prior to export.

6. Place of Inspection.—Inspection of seel and steel products for the purposes of these rules shall be carried out—

(a) at the premises of the manufacturer, or

(b) at the premises at which the steel and steel products are offered by the exporter provided adequate testing facilities for the purpose exist therein.

7. Inspection Fee.—A fee at the rate of Rs 1.50 per tonne subject to a minimum of rupees one hundred shall be paid by exporter to the Agency as inspection fee under these rules.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by he refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4 may within ten days of receipt of communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two thirds of the total membership of the panel of experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum of the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

[No. 6(7)/76-E I & E P.]

का० आ० 480.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3030, तारीख 20 सितम्बर, 1965 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची I के स्तम्भ (1) में वर्णित संगठनों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट हल्के इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात से पूर्व उनके निरीक्षण के लिए अभिकरणों के रूप में इस शर्त पर मान्यता देती है कि ऐसा प्रत्येक संगठन, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत परिषद् के अधिकारी को हल्के इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976 के नियम 4 के उप-नियम (5) के अधीन प्रमाण-पत्र देने के लिए, इस संगठन द्वारा अपनाई गई निरीक्षण पद्धति निरीक्षण कर सकने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगी।

टिप्पण—भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 895 तारीख 21 फरवरी, 1976 के अनुसार जिन हल्के इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण किया जाएगा उनकी सूची इससे उपाबद्ध अनुसूची II में दी गई है।

अनुसूची I

संगठन का नाम तथा पता	वस्तुएं
1	2
1. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन	अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट सभी हल्के इंजीनियरी उत्पाद
2. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मद्रास	
3. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कलकत्ता	
4. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली	
5. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई	
6. मैसर्स इन्सपैक्शन एंड टेस्टिंग कं० (इंडिया) प्रा० लि०, पी-1, हाइड लेन, कलकत्ता-12	
7. मैसर्स मित्रा एस० के० प्रा० लि०, पी-11, सी० आई० टी० रोड, कलकत्ता-14	अनुसूची 2 में घरेलू वस्तुओं के अन्तर्गत, बर्नर सहित लालटेन, को छोड़कर विनिर्दिष्ट सभी हल्के इंजीनियरी उत्पाद
8. मैसर्स लायड्स रजिस्टर ग्राफ शिपिंग, 1, फेयरली प्लेस, कलकत्ता-1	
9. मैसर्स कामो इंसपैक्टर्स एंड सुपरिटेन्डेन्स कं० प्रा० लि० एलिस बिल्डिंग, डा० दादा भाई नौरोजी रोड, बम्बई-1	
10. मैसर्स सुपरिटेंडेन्स कं० आफ इन्डिया (प्रा०) लि० 46 सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता	
11. मैसर्स एन० सी० कारपोरेशन प्रा० लि०, 'स्टेडियम हाऊस', (चौथी मंजिल) 81—83, वीरनारीमन रोड, मुम्बई-1	
12. मैसर्स एम० एन० दस्तूर एंड कं० प्रा० लि०, कंसल्टिंग इन्जीनियर्स, पी-17 मिशन रो एक्सटेंशन, कलकत्ता-13	
13. आफिसर इन्चार्ज, क्वालिटी मार्किंग सेंटर्स (इंजि) मालेरकोटला, बटाला, लुधियाना, जलन्धर तथा अमृतसर में उद्योग निदेशालय, पंजाब	
14. आफिसर इंचार्ज क्वालिटी मार्किंग सेंटर्स (इंजि), फरीदाबाद, सोनीपत, जगाधरी तथा अम्बाला में उद्योग निदेशालय, हरियाणा	
15. क्वालिटी मार्किंग सेंटर्स, अलीगढ़, मेरठ तथा मुरादाबाद में उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश	(1) पीतल के बर्तन (2) तांबे के बर्तन (3) कैंचियां (4) दराज के ताले, अलमारी के ताले, बक्सों के ताले, सूटकेस के ताले, पोर्टफोलियो के ताले तथा ब्रीफ केस के ताले (5) मार्टिस ताले (उभय प्रकार के) (6) पैडलाक ताले

अनुसूची-II

हल्के इंजीनियरी उत्पाद

1 घरेलू वस्तुएं

1 पीतल के बर्तन

2 बर्नर सहित ब्लो लैंप

3 ताबे के बर्तन

4 नरम लोहे की बाल्टियां

5 बर्नर सहित तेल के दबाव वाले स्टोव

6 तेल के दबाव वाली लालटेन

7 कैंचियां

8 छाते

2 हमारी सामान

1 दराजों के ताले, अलमारी के ताले, बक्सों के ताले, सूटकेस के ताले, पोर्टफोलियो के ताले तथा ब्रीफकेस के ताले।

2 बाड़ लगाने के लिए जस्तीकृत इस्पात का कंटीला तार

3 तसले

4 कब्जे

5 नरम इस्पात के तार की कील

6 मार्टिस ताले (उत्तम प्रकार के)

7 पैडलाक ताले

8 पैडलाक तालों के साथ लगने वाले दरवाजों के सरकवां कुण्डे

9 चटकनियां

10. तार की जाली

3 कांटे छुरियां

1 कांटे

2 चाकू

3 चम्मच

[सं० 6(14)/74-नि०नि० तथा नि०उ०]

S.O. 480.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in super-session of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce No S O 3030 dated the 20th September, 1965, the Central Government hereby recognises the organisations mentioned in column (1) of Schedule I annexed hereto as the agencies for the inspection of the light engineering products specified against each in column (2) of the said schedule, prior to their export, subject to the condition that every such organisation shall give adequate facilities to an officer of the Export Inspection Council, duly authorised by the Council, to inspect the method of inspection followed by that organisation in granting the certificate under sub-rule (5) of rule 4 of the Export of Light Engineering Products (Inspection) Rules, 1976

Note —A list of the Light Engineering Products which shall be subject to inspection prior to export vide the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No S O 895 dated the 21st February, 1976 is in Schedule II annexed hereto

SCHEDULE I

	Name and address of the Organisation	Item
1	Export Inspection Agency, Cochin	All light engineering products specified in schedule II
2	Export Inspection Agency, Madras	
3	Export Inspection Agency, Calcutta	
4	Export Inspection Agency, Delhi	
5	Export Inspection Agency, Bombay	
6	M/s Inspection Testing Co (India) (P) Ltd P 1, Hide lane, Calcutta-12	All light engineering products specified in Schedule II excepting '2 Blow lamp including burner' under '1 Household Articles'
7	M/s Mitra S K (P) Ltd, P-II, C I T Road, Calcutta-14	
8	M/s Lloyds Register of Shipping, 1, Fairlie Place Calcutta 1	
9	M/s Cargo Inspectors and Superintendence Co (P) Ltd, Alice Buildings, Dr Dadabhai Naroji Road Bombay-1	
10	M/s Superintendence Co of India (P) Ltd, 46C, Chowringhee Road Calcutta	
11	M/s N C, Corporation Pvt Ltd 'Stadium House' (3rd Floor), 81-83 Veer Narman Road, Bombay-1	
12	M/s M N Dastur and Co, P Ltd, Consulting Engineers, P-17, Mission Row Extension, Calcutta-13	
13	Officers-in-charge, Quality Marking Centres (Eng) Directorate of Industries, Punjab at Malerkotla, Batala, Ludhiana, Jullunder and Amritsar	
14	Officers-in-charge, Quality Marking Centres (Eng) Directorate of Industries, Haryana at Faridabad, Sonepat, Jagadhri and Ambala	
15	The Quality Marking Centres, Directorate of Industries, Uttar Pradesh, at Aligarh, Meerut and Moradabad	(1) Brass utessils (2) Copper utensils (3) Scissors (4) Drawer locks, Cupboard locks, box locks, suitcase locks, portfolio locks and Brief case locks (5) Mortice locks (vertical type) (6) Padlocks

SCHEDULE II

LIGHT ENGINEERING PRODUCTS

I Household Articles

1 Brass utensils
2 Blow lamp including burner
3 Copper utensils
4 Mild steel buckets
5 Oil pressure stove including burner
6 Oil pressure lantern
7 Scissors
8 Umbrellas

II Builder's Hardware

1 Drawer locks, cupboard locks, box locks, suitcase locks, portfolio locks and briefcase locks
2 Galvanised steel barbed wire for fencing
3 Ghamellas
4 Hinges
5 Mild steel wire nails
6 Mortice locks (vertical type)
7 Padlocks

8. Sliding door bolts for use with padlocks
9. Tower bolts
10. Wire gauze

III. Cutlery

1. Forks
2. Knives
3. Spoons.

[No. 6(14)/74/EI & EP]

का० आ० 481.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार विश्लेषण प्रयोगशाला, जाजपुर रोड (जिला कटक) तथा जोड़ा (जिला कियोनझर) को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3150 दिनांक 30 सितम्बर, 1965 से उपाबद्ध अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क-ग्रुप 2 के निरीक्षण के लिए अभिकरण के रूप में एक वर्ष की और अवधि के लिए एतद्वारा मान्यता देती है।

[सं० 5(4)/74-ई०आई०एण्ड ई०पी०]

S.O. 481.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises for a further period of one year the Government of Orissa Analytical Laboratories at Jajpur Road (District : Cuttack) and Joda (District : Keonjhar) as the agency for the inspection of the Minerals and Ores—Group II, specified in Schedule II annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3150 dated the 30th September, 1965.

[No. 5(4)/74-FI & EP]

का० आ० 482.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार विश्लेषण प्रयोगशाला, जाजपुर रोड (जिला कटक) तथा जोड़ा (जिला कियोनझर) को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3152 तारीख 30 सितम्बर 1965 के उपाबद्ध अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क-ग्रुप 1 के निरीक्षण के लिए अभिकरण के रूप में एक वर्ष की और अवधि के लिए एतद्द्वारा मान्यता देती है।

[सं० 5(4)/74-ई०आई० एण्ड ई०पी०]

के० वी० बालसुब्रमणि, यस, उप निदेशक

S.O. 482.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year the Government of Orissa Analytical Laboratories at Jajpur Road (District : Cuttack) and Joda (District : Keonjhar), as the agency for the inspection of the Minerals and Ores—Group I, specified in Schedule II annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 3152 dated the 30th September, 1965

[N. 5(4)/74-EI & EP]

K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy Director

(निर्यात उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1977

रबड़ नियंत्रण

का० आ० 483.—रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के साथ पठित, रबड़ अधिनियम 1947 (1947 का 24) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि संसद सदस्य श्रीमती लीला दामोदर मेनन को उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) के अधीन सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य परिषद् द्वारा रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है।

[फा० सं० 15(4)/70-प्लांट (बी)]

श्रीमती कोमल आनन्द, अवर सचिव

(Department of Export Production)

New Delhi, the 24th January, 1977

RUBBER CONTROL

S.O. 483.—In xercise of the powers conferred by section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), read with rule 4 of the Rubber Rules, 1955, the Central Government hereby notifies that Smt. Leela Damodara Menon, Member of Parliament, has been elected by the Council of States as a member of the Rubber Board, under clause (e) of sub-section (3) of section 4 of the said Act for a period of three years from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. 15(4)/70-Plant(B)]

SMT. KOMAL ANAND, Under Secy.

मुख्य-नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1977

का० आ० 484.—सर्वश्री पंजाब ग्रीवरीज लि० फोकल प्वाइन्ट एरिया, लुधियाना को 17,000/- रुपये (सतरह हजार रुपये मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या आई/डी/1069239/आर /एमएल/एच/59/41-42, दिनांक 14-5-76 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह उल्लेख किया गया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत नहीं कराई गई थी।

इस का किसी भी धनराशि के लिए उपयोग नहीं किया गया था और इस पर 2-12-1976 को 17,000/- रुपये का उपयोग करना बाकी था।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने शपथ अधिकारी लुधियाना से एक प्रमाणपत्र के साथ एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है। इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-55 की उप-धारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री पंजाब ग्रीवरीज लि०, लुधियाना को जारी किए गए लाइसेंस संख्या आई/डी/1069239/आर/एम एल/एच/59/41-42, दिनांक 14-5-76 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि लाइसेंस धारी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या पी०/3/75-76/पी०एस०एल०(ए)]

लक्ष्मीश्वर प्रसाद, उप मुख्य नियंत्रक

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

ORDER

New Delhi the 27th January, 1977

S.O. 489.—M/s. Punjab Breweries Limited, Focal Point Area, Ludhiana were granted an import licence No. I/D/1069239/R/ML/59/41-42, dated 14-5-76 for Rs. 17,000/- (Rupees Seventeen thousand only). They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control Purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Exchange Control copy was not registered with any Custom authorities.

It was utilised for Rs. Nil and the balance available on it was Rs. 17,000/- as on 2-12-1976.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from Oath Commisioner Ludhiana. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-55, as amended the said original Exchange Control Purposes copy of licence No. I/D/1069239/R/ML/H/59/41-42 dated 14-5-76 issued to M/s Punjab Breweries Limited, Ludhiana is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licencee.

[No. P/3/75-76/PLS(A)]
L. PRASAD, Dy. Chief Controller

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय

कलकत्ता, 16 सितम्बर, 1976

का० आ० 485 :—सर्वश्री बंगाल टूलज लि० 251/17 नगेन्द्रनाथ रोड डम-डम कलकत्ता-28 को 20,761 रुपए के लिए ला०सं० पी०/एस०/1776128/सी०/एक्स०एक्स०/52/सी०/37-38 दि० 31-7-74 प्रदान किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस खो गया/अस्थानस्थ हो गया है। आगे बताया गया है कि मूल लाइसेंस सीमा शुल्क समाहर्ता, सीमा शुल्क कार्यालय कलकत्ता-700001 में पंजीकृत कराया गया था और 10,380 रुपए मात्र के मूल्य और साथ में 5,790 रुपए जो अप्रैल-मार्च 1976 की लाइसेंस अवधि के लिए 50 प्रतिशत पुनः परिचालन के कारण हैं, के लिए प्रयोग कर लिया गया है। अब अनुलिपि लाइसेंस की आवश्यकता अप्रयुक्त मूल्य 10,380 रुपए के लिए है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने इस संबंध में एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं सन्तुष्ट हूं कि ला०सं० पी०/एस०/1776128/सी० दि० 31-7-74 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ हो गई/खो गई है और इसलिए निदेश देता हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जाए। तदनुसार उपर्युक्त ला० की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

[सं० ए०यू०/134007/13/ए०एम०-74/4/504]
के० पी० नारायण, उप मुख्य नि०

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Calcutta, the 16th September, 1976

S.O. 485.—M/s. Bangal Tools Ltd., of 251/17 Nagendra Nath Road, Dam Dam, Calcutta-28 were granted licence No. P/S/1776128/C/XX/52/C/37-38 dated 31-7-74 for Rs. 20,761. They have applied for duplicate Custom Purpose Copy of the said licence on the ground that the original licence has been lost/misplaced. It is further stated that the original licence had been registered with Collector of Customs, Custom House, Calcutta-700001 and utilised for a value of Rs. 10,380 only plus Rs. 5,790 being 50 per cent repeat operation for the licensing period of April-March 1975. The duplicate licence now required is for the unutilised value of Rs. 10,380.

In support of the contention the applicant has filed an affidavit to this effect. I am satisfied that the original Customs purpose copy of licence No. P/S/1776128/C dated 31-7-74 has been misplaced/lost and so direct that a duplicate copy of the said licence be issued to the applicant. Accordingly the original customs copy of the said licence is cancelled.

[No. AU/134007/13/AM-74/IV/504]
K. P. NARAYAN, Dy. Chief Controller

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 22 जनवरी, 1977

का० आ० 486:—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की 1 जनवरी, 1975 की अधिसूचना संख्या 1(1)/73-खान-6 के क्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 31 दिसम्बर, 1978 की ऐसी तारीख का समय निर्धारित करती है जिस तक खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम 1972 के प्रारम्भ से पूर्व स्वीकृत सभी खनन पट्टे, यदि ये अधिनियम के प्रारम्भ के समय विद्यमान थे, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कर दिए जाएंगे।

[सं० 1(50)/76-खान-6]
आर० के० नायक, उप सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

ORDER

New Delhi, the 22nd January, 1977

S.O. 486.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 16 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. 1(1)/73-M. VI dated the 1st January, 1975, the Central Government hereby specifies the 31st December, 1978 as the date within which all mining leases granted before the commencement of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Act, 1972, if in force at such commencement, shall be brought into conformity with the provisions of the said Act and the rules made thereunder.

[No. 1(50)/76-M. VI]
R. K. NAYAK, Dy. Secy.

नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1977-01-19

का० आ० 487—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि एकनेत्र विच्छेदी सूक्ष्मदर्शी की प्रति इकाई प्रमाणन चिह्न लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है और यह फीस 1976-01-01 से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
1	2	3	4	5
1	एकनेत्र विच्छेदी सूक्ष्मदर्शी	IS 4328—1967 एकनेत्र विच्छेदी सूक्ष्मदर्शी की विशिष्टि।	एक सूक्ष्मदर्शी	(1) पहली 100 इकाइयों के लिए रु० 5 00 प्रति इकाई और (2) 101वीं और इससे ऊपर की इकाइयों के लिए रु० 2 00 प्रति इकाई।

[संख्या सी एम डी/13 10]

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 1977-01-19

S.O. 487.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the marking fee per unit for monocular dissecting microscope details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1976-01-01

SCHEDULE

Sl No	Product/Class of Product	No and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
1	2	3	4	5
1	Monocular dissecting microscope	IS 4328-1967 Specification for monocular dissecting microscope	One Microscope	(i) Rs 5 00 per unit for the first 100 units and (ii) Rs 2 00 per unit for the 101st units and above

[No CMD/13 10]

का० आ० 488—भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिह्न निर्धारित किए हैं जिनकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त यह मानक चिह्न 1976-01-01 से लागू होगा

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
1	2	3	4	5
1	IS 4328	एकनेत्र विच्छेदी सूक्ष्मदर्शी	IS 4328—1967 एकनेत्र विच्छेदी सूक्ष्मदर्शी की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।

[संख्या सी एम डी/13 9]

S.O. 488.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1976-01-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
1.	IS : 4328	Monocular dissecting microscope	IS : 4328-1967 Specification for monocular dissecting microscope	The monogram of the Indian Standards Institution consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Co.1 (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

का० आ० 489—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि एक ब्लाक वाले पम्प सेटों की प्रति इकाई प्रमाणन चिन्ह लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है और यह फीस 1971-10-16 से लागू होगी.

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
1	2	3	4	5
1.	एक ब्लाक वाले पम्प सेट	IS : 6595—1972 खेती कार्यों में ठंडे, साफ और ताजे पानी की सप्लाई के लिए क्षैतिज अपकेन्द्रीय पम्पों की विशिष्टि और IS: 7538—1975 खेती कार्यों में उपयोग के लिए तीन फेजी स्क्वीरेल केज प्रेरण मोटर की विशिष्टि।	एक-एक ब्लाक वाला पम्प	रु० 2 00

[संख्या सी एम डी/13 10]

S.O.489.—In persuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the marking fee per unit for monoblock pumpsets details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1976-10-16:

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
1	2	3	4	5
1.	Monoblock pumpsets	IS : 6595-1972 Specification for horizontal centrifugal pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes with IS:7538-1975 Specification for three-phase squirrel cage induction motors for agricultural application	One Monoblock pump	Rs. 2.00

[No. CMD/13 : 10]

का० आ० 490 --भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिह्न निर्धारित किए हैं जिनकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त ये मानक चिह्न 1976-10-16 से लागू होगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
1	2	3	4	5
1	IS : 6595	एक ब्लाक वाले पम्प सेट	IS : 6595--1972 खेती कार्यों में, साफ और ताजे पानी की सप्लाई के लिए क्षैतिज अपकेन्द्रीय पम्पों की विशिष्टि और IS : 7538--1975 खेती कार्यों में उपयोग के लिए तीन फेजी स्क्वीरेल केज प्रेरण मोटर की विशिष्टि।	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'IS' शब्द होते है, स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर और शब्द और अंक 'IS : 6595' तथा मोनोग्राम के नीचे की ओर शब्द और अंक "IS : 7538" अंकित किए गए है।

[संख्या सी एम डी/13 : 9]

S. C. 490.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1976-10-16 :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
1.	IS : 6595	Monoblock pumpsets	IS : 6595-1972 Specification for horizontal centrifugal pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes with IS:7538-1975 Specification for three-phase squirrel cage induction motors for centrifugal pumps for agricultural application.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the letters and figures 'IS : 6595' being superscribed on the top side and the letters and figures 'IS : 7538' being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

नई दिल्ली, 1977-01-20

का० आ० 491 --समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे अब वापस ले लिए गए हैं और रद्द माने जाएं।

अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या और शीर्ष	भारत के राजपत्र की एसओ संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक के तैयार होने की सूचना छपी थी	विवरण
1	2	3	4
1.	IS : 3379--1965 कुसुम के बीज की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1966-06-11 में एस ओ 1756 दिनांक 1966-05-30 के अन्तर्गत प्रकाशित।	कुसुम और तम्बाकू के बीजों सम्बन्धी प्रमाणन मानकों को भारत सरकार के बीज अधिनियम, 1966 में शामिल कर लिए जाने के फलस्वरूप रद्द कर दिए गए है।
2	IS : 3380--1965 तम्बाकू के बीज की विशिष्टि		

[संख्या सी एम डी/13 : 7]

ए० बी० राव, उप महानिदेशक

New Delhi, the 1977-01-20

S.O. 491.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulations of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time, it is hereby, notified that the Indian Standards, particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have been cancelled and stands withdrawn:—

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O.No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
1 2.	IS:3379-1965 Specification for safflower seeds IS:3380-1965 Specification for tobacco seeds	S.O. 1756 dated 1966-05-30— published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1966-06-11	Cancelled as the Certification Standards for safflower seeds and tobacco seeds are being included under the Seeds Act, 1966 of Government of India.

[No. CMD/13:7]
A. B. RAO, Dy. Director General

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1977

का० आ० 492.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन पेपर एण्ड जिंजर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन लि० बम्बई द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को महाराष्ट्र राज्य में लागू बम्बई जनरल क्लाजेज एक्ट, 1904 (बम्बई एक्ट आफ 1904) में यथापरिभाषित वृहत बम्बई की सीमान्तर्गत काली मिर्च की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 19 जनवरी, 1977 से 18 जनवरी, 1978 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित है) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2 एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाए ।

[सिमिल संख्या 12(27)-आई० टी०/76]

New Delhi, the 2nd February, 1977

S.O. 492.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Pepper & Ginger Merchants' Association Ltd., Bombay and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 19th January, 1977 to the 18th January, 1978 (both days inclusive) in respect of forward contracts in pepper within the limits of Greater Bombay as defined in the Bombay General Clauses Act, 1904 (Bombay Act I of 1904), as in force in the State of Maharashtra.

The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission

[F. No. 12(27)-IT/76]

का० आ० 493.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सुरेन्द्र नगर काटन आयल एंड आयल सीड एसोसियेशन लि०, सुरेन्द्र नगर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसियेशन को कपास की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 23 नवम्बर, 1976 से 22 नवम्बर, 1977 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित है) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसियेशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाए ।

[सिमिल संख्या 12(25)-आई० टी०/76]

S.O. 493.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Secton 5 of the Forward Costracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by he Surendranagar Cotton oil and Oilseeds Association Ltd., Surendranagar.

And being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest so to do,

Hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 23rd November, 1976 to the 22nd November, 1977 (both days inclusive), in respect of forward contracts in Kapas.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12(25)-IT/76]

का० आ० 494.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सेन्ट्रल इण्डिया कमर्सियल एक्सचेंज लिमिटेड, ग्वालियर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुड़ की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 26 नवम्बर, 1976 से 25 नवम्बर, 1977 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2 एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं ।

[मिसिल संख्या 12(22)-आई० टी०/76]

S.O. 494.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Secton 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Central India Commercial Exchange Limited, Gwalior,

And being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest so to do,

Hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from 26th November, 1976 to the 25th November, 1977, (both days inclusive), in respect of forward contracts in gui

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association, shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(22)-IT/76]

का० आ० 495.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन हांसी पंजाब कमर्सियल एक्सचेंज लिमिटेड, हांसी द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को बिनौला की अग्रिम संविदाओं के बारे में 13 जनवरी, 1977 से 12 जनवरी 1978 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2 एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाएं ।

[मिसिल संख्या 12(24)-आई० टी०/76]

S.O. 495.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Hansi Punjab Commercial Exchange Ltd., Hansi,

And being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest so to do,

Hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 13th January, 1977 to the 12th January, 1978, (both days inclusive), in respect of forward contracts in cottonseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(24)-IT/76]

का० आ० 496.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन लुधियाना ग्रैन एक्सचेंज लिमिटेड, लुधियाना द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को बिनौले की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 12 दिसम्बर, 1976 से 11 दिसम्बर, 1977 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2 एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-पर दिए जाएं ।

[मिसिल संख्या 12(23)-आई० टी०/76]

ए० मुबई, उप सचिव

S.O. 496.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Ludhiana Grain Exchange Limited, Ludhiana,

And being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest so to do,

Hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 12th December, 1976 to the 11th December, 1977, (both days inclusive), in respect of forward contracts in cottonseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(23)-IT/76]

A. MUBAYI, Dy. Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1977

का० आ० 97.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश सं० का०आ० 1047, तारीख 24 फरवरी, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् —

उक्त आदेश की अनुसूची में :—

(i) "भाग I साधारण केन्द्रीय सेवा-समूह ग, भारतीय सर्वेक्षण" में, क्रम सं० 2 के पद के सामने, स्तंभ (3) में, मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :— (ii)

उपनिदेशक/कार्यालय-प्रधान (जो भारसाधक उपअधीक्षण सर्वेक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो) / उप भंडार अधिकारी / भारसाधक अधिकारी, मानचित्र अभिलेख और निर्गम कार्यालय।"

(ii) "भाग II साधारण केन्द्रीय सेवा-समूह घ, भारतीय सर्वेक्षण" में, क्रम सं० 2 के पद के सामने स्तंभ (2) में और स्तंभ (3) की मद (i) में "भारसाधक अधिकारी सर्वेक्षक" शब्दों के स्थान पर "भारसाधक उप अधीक्षण सर्वेक्षक" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 18-107/75-सर्वेक्षण I]
टी० एल० विश्वनाथन, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

ORDER

New Delhi, the 28th January, 1977

S.O. 497.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India, Department of Science and Technology, No. S.O. 1047, dated the 24th February, 1976, namely :—

In the schedule to the said Order :—

(i) in "Part-I General Central Service—Group C, Survey of India", against the post at serial No. 2, incolumn. (3), in item (ii), for the words and brackets "Head of Office (not below the rank of Officer Surveyor-in-charge)", the words and brackets "Head of Office (not below the rank of Deputy Superintending Surveyor-in-charge)" shall be substituted;

(ii) in "Part-II General Central Service—Group D, Survey of India", against the post at serial No. 2, in column (2) and in item (i) of column (3), for the words and brackets "Head of Office (not below the rank of Officer Surveyor-in-Charge)", the words and brackets "Head of Office (not below the rank of Deputy Superintending Surveyor-in-charge)", shall be substituted.

[No. 18-107/75-Sur. I]
T. L. VISWANATHAN, Under Secy.

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1977

का० आ० 498.—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 5152 तारीख 17.11.75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बन्धनों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रुद्रसागर कूप नम्बर 81 से रुद्रसागर जी० जी० एस० नम्बर 2 तक की पाइप लाइन

राज्य : असम | जिला : शिवसागर | तालुक : मेलेका बनगांव

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सन्ती-ऐरे
1	2	3	4	5
लाहिगीया	346ख		2	81
	426ख		0	27
	425ख		1	34
	424ख		8	96
	423ख		1	20
	347ख		2	54
	348ख		0	13
	283ख		1	47
	282ख		1	61
	281ख		1	61
	280ख		1	74
	279ख		1	74
	429ख		1	34
	410ख		1	34
	428ख		1	34
	352ख		1	61
	353ख		2	68
	368ख		2	01

[सं० 12020/4/75-एल० एण्ड एल०II]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 21st January, 1977

S.O. 498.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S. O. No. 5152 dated 17-11-75 under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the competent Authority has under Sub-Section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by Sub-Section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline (Feeder Line) From Rudrasagar Well No. 81 To Rudrasagar GGS No. 2.

State . Assam Dist : Sibsagar Taluk : Metekabongaon

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Lahingia	346 Kha	0	2	81
	426 Kha	0	0	27
	425 Kha	0	1	34
	424 Kha	0	8	96
	423 Kha	0	1	20
	347 Kha	0	2	54
	348 Kha	0	0	13
	283 Kha	0	1	47
	282 Kha	0	1	61
	281 Kha	0	1	61
	280 Kha	0	1	74
	279 Kha	0	1	74
	429 Kha	0	1	34
	410 Kha	0	1	34
	428 Kha	0	1	34
	352 Kha	0	1	61
	353 Kha	0	2	68
	368 Kha	0	2	01

[No. 12020/4/75-L & L-III]

का० आ० 499.—यत. पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० स० 5150 तारीख 17-11-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संपटकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रुद्रसागर जी० जी० एस नम्बर 1 से लकवा जी० जी० एस नम्बर 1 तक की पाइपलाइन।

राज्य . आसाम जिला : शिवसागर तालुक : शिलाकूटी

ग्राम	सर्वेनम्बर	हैक्टर	ऐरे	सेन्टीऐरे
धोराचोवा	622 ग	0	4	01
	641 ख	0	1	07
	642 ग	0	0	94
	623 ख	0	0	27
	559 ग	0	2	94
	639 ख	0	2	41
	624 ख	0	0	27
	640 ख	0	2	54
	627 ख	0	1	20
	625 ख	0	0	94
	626 ख	0	6	56
	643 ख	0	9	77
	637 ख	0	2	94
	637 क	0	0	27
	330 ख	0	11	64

[सं० 12020/4/75-एल० एण्ड एल०-I]
टी० पी० सुब्रह्मनियम, अवर सचिव

S.O. 499.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 5150 dated 17-11-75 under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by Sub-Section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from Rudrasagar GGS No 1 to Lakwa GGS No 1
State : Assam Dist . Sibsagar Taluk Silakuti

Village	Survey No	Hectare	Are	Cectiare
Ghorachowa	622/Ga	0	4	01
	641/Kha	0	1	07
	642/Ga	0	0	94
	623/Kha	0	0	27
	559/Ga	0	2	94
	639/Kha	0	2	41
	624/Kha	0	0	27
	640/Kha	0	2	54
	627/Kha	0	1	20
	625/Kha	0	0	94
	626/Kha	0	6	56
	643/Kha	0	9	77
	637/Kha	0	2	94
	637/Unga	0	0	27
	630/Kha	0	11	64

[No 12020/4/75-L & L-I]
T P SUBRAHMANYAN, Under Secy

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1977

का० आ० 500—पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59) की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा के सहायक महानिदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य) डा० पी० एन० सहगल को डा० महेन्द्र दत्त के स्थान पर उनके सामने दी गई तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिये पशु कल्याण मण्डल का सदस्य मनोनीत करते हैं —

सदस्य	तारीख	अवधि	श्रेणी
1 डा० पी० एल० सहगल	24-12-1976	3 वर्ष धारा	5(1)(घ) चिकित्सा की आधुनिकी प्रणाली प्रस्तुत करना।

[संख्या 14-27/73-एल० डी० I]
जे० पी० भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 22nd January, 1977

S.O. 500.—Under provisions of sub-section (1) of section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby nominates Dr P N Sehgal, Assistant Director General (Public Health), Directorate General of Health Services in place of Dr Mahendra Dutt, to be the member of the Animal welfare Board as under —

Member	Date	Period	Category
1 Dr P N Sehgal	24 12 76	3 years	Section 5 (1) (d) Representing the modern system of medicine

[No 14-27/73-L D I]
J P BHATNAGAR, Under Secy

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1977

का० आ० 501—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के खंड 5 के उपखंड (3) की धारा (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा डा० ए० एस० चीमा, कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना को, प्रो० जे० बी० चितम्बर के स्थान पर जिनका कार्यकाल 2 जनवरी, 1977 को समाप्त हो गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 16-89/76-एल० यू०]
अनिल बार्डिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

New Delhi, the 25th January, 1977

S.O. 501.—In exercise of the powers conferred by Clause (c) of Sub-Section (3) of Section 5 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) the Central Government hereby appoints Dr A S Cheema, Vice-Chancellor, Punjab Agricultural University, Ludhiana as a Member of the University Grants Commission for a term of three years with immediate effect vice Prof. J B Chitambar, whose term expired on 2nd January, 1977

[No F. 16 89/76-Leg Unit]
ANIL BORDIA, Jt Secy

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1977

का० आ० 502.—वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपनी यह राय होने के कारण कि लोक सुरक्षा के हित में ऐसा करना समीचीन है, आदेश करती है कि 1 जनवरी, 1977 से दो वर्ष तक की अवधि तक कोई वायुयान, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विशेष अनुज्ञापत्र की शर्तों और निबंधनों के अधीन और उनके अनुसरण में के सिवाय, निम्नलिखित क्षेत्रों में या उनके ऊपर कोई उड़ान नहीं भरेगा, अर्थात् —

(i) अरुणाचल प्रदेश (जिसे पहले उत्तर पूर्व सीमा एजेंसी कहा जाता था), नागालैंड और मिजोरम (जिसे पहले मिजो पहाड़ी जिला कहा जाता था)

(ii) मणीपुर पूर्वी जिला (जिसे पहले उखरुल उप-खंड कहा जाता था),

(iii) मणीपुर केन्द्रीय जिला (जिसे पहले लेंगनोपाल उप-खंड कहा जाता था),

(iv) मणीपुर दक्षिणी जिला (जिसे पहले मुराचांदपुर उप-खंड कहा जाता था)।

[फा० सं० ए०वी० 11013/2/76 ए०/ए०आर०/1937 (1)/1977]
एम० एकाम्बरम, उप सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 24th January, 1977

S.O. 502—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 6 of the Aircraft Act,

1934 (22 of 1934), the Central Government, being of opinion that it is expendient in the interest of public safety to do so, hereby orders that for a period of two years from the January 4, 1977, no arcraft shall, except under and in accordance with the terms and conditions, of a special permit issued by the Government of India in the Ministry of Defence, make flights into or over the following areas, namely:—

(i) Arunachal Pradesh (previously known as North East Frontier Agency), Nagaland and Mizoram (previously known as Mizo Hills District) ;

(ii) Manipur East Distrct (previously known as Ukhrul sub-division) ;

(iii) Manipur Central District (previously known as Tengnoupal Sub division) ;

(iv) Manipur South District (previously known as Churachandpur Sub Divisison).

[F. No. AV. 11013/2/76/-A/AR/1937(1)/1977]

S. EKAMBARAM, Dy. Secy.

निर्माण और आवास मन्त्रालय

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977

का०आ० 503.—यतः कतिपय उपान्तरण, जिन्हें केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों के सम्बन्ध में दिल्ली की बृहत्त योजना में करने की प्रस्थापना करती है ; दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसरण में, सूचना सख्या एफ० 20(7)/76-यू० यो० दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित ; प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उक्त सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे :—

और यतः उपर्युक्त उपान्तरण के बारे में कोई आक्षेप तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11(क) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली की बृहत्त योजना में, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित उपान्तरण करती है, अर्थात् :—

"मानसिंह रोड तथा मोतीलाल नेहरू मार्ग के चौराहे पर 1.618 हेक्टेयर (4 एकड़) आकार का क्षेत्रफल (1, मानसिंह रोड) जिसको बृहत्त योजना में 'रिहायशी उपयोग' के लिए निश्चित किया गया है, को 'वाणिज्यिक (होटल) उपयोग' के लिए बदलने का प्रस्ताव है।"

[सं० के०-13014(4)/71-यू० डी० आई०]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 31st January, 1977

S.O 503.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published with notice No F. 20(7)/76-MP, dated the 16th October 1976 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections and suggestions, as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of said notice;

And where no objections or suggestions have been received with regard to the aforesaid modifications;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this modification in the Gazette of India, namely :—

"An area (1-Man Singh Road) measuring 1.618 hectares (4 acres), earmarked for 'residential use' in the Master Plan at the crossing of Man Singh Road and Moti Lal Nehru Marg, is proposed to be changed to 'commercial (Hotel) use'."

[No. K-13014(4)/71-UDI]

का० आ० 504.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार यतः कतिपय उपान्तरण, जिन्हें केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों के सम्बन्ध में दिल्ली की बृहत्त योजना में करने की प्रस्थापना करती है, सूचना सं० एफ० 20(7)/76 एम० पी० दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (3) द्वारा यथापेक्षित प्रकाशित किए गये थे, जिसमें उक्त सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और यतः उपर्युक्त उपान्तरण के बारे में कोई आक्षेप तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए,

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11(क) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली की बृहत्त योजना में, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित उपान्तरण करती है, अर्थात् :—

"जनपथ और अशोका रोड के चौराहे पर विण्डसर प्लेस के दक्षिण में जोन डी-3 (कर्जन रोड क्षेत्र) के लिए बृहत्त योजना जानल विकास प्लान में रिहायशी प्रयोग के लिए निर्धारित 1.821 हेक्टेयर (4.5 एकड़) क्षेत्र को 'वाणिज्यिक (होटल) प्रयोग' में बदला जाना प्रस्तावित है।

जनपथ और रायसीना रोड के चौराहे पर विंडसर प्लेस के दक्षिण में जोन डी-4 (पार्लियामेंट स्ट्रीट) के लिए बृहत्त योजना जानल विकास प्लान में रिहायशी उपयोग के लिए निर्धारित लगभग 1.821 हेक्टेयर (4.5 एकड़) क्षेत्र को 'वाणिज्यिक (होटल) उपयोग' में बदलने का प्रस्ताव है।"

[सं० के-13011(40)/76-यू० डी० आई० (ए)]

S.O. 504.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 20(7)/76-MP, dated the 16th Octobeiber 1976 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said Notice;

And whereas no objections or suggestions have been received with regard to the aforesaid modifications;

Now, therefore, in exercise of the powers conferrd by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely :—

"An area measuring 1.821 hects. (4.5 acres) earmarked for 'residential use' in the Master Plan/Zonal Development Plan for Zone D-3 (Curzon Road area) in the South of Windsor Place, at the crossing of Janpath and Ashoka Road, is proposed to be changed to 'commercial (Hotel) use'.

An area measuring about 1.821 hects. (4.5 acres), earmarked for 'residertial use' in the Master Plan/Zone Develpoment Plan for Zone D-4 (Parliament Street), in the South of Windsor Place, at the

crossing of Janpath and Raisina Road, is proposed to be changed to 'commercial (Hotel) use'"

[No. K-13011(40)/76-UDI(A)]

का० आ० 505.—यतः कतिपय उपान्तर, जिन्हें केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में दिल्ली की बृहत्त योजना में करने की प्रस्थापना करती है दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसरण में, सूचना सं० एफ० 16(22)/75-बृ० यो० दिनांक 20 फरवरी, 1976 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ।

और यतः उपर्युक्त उपान्तरण के बारे में कोई आक्षेप तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11(क) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली की बृहत्त योजना में, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित उपान्तरण करती है, अर्थात् :—

"प्लाट सं० 62, ब्लाक 'एल', दयानन्द मार्ग, दरियागंज, जिसका आकार लगभग 303 5 वर्गमीटर (363 व० गज) है तथा जो जोन ए-20 (नया दरियागंज) में आता है, के भू उपयोग को 'रिहायशी' से 'वाणिज्यिक' (स्थानीय शापिंग) में बदलने का प्रस्ताव है । यह प्लाट उत्तर में दयानन्द मार्ग, दक्षिण में रिहायशी क्षेत्र, पूर्व में प्लाट सं० 62-ए और पश्चिम में लेख राम मार्ग से घिरा हुआ है ।"

[सं० के-13012(3)/72-यू० डी०आई० (ए)]

S.O. 505.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 16(22)/75-MP, dated the 20th February, 1976 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections and suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said Notice ;

And whereas no objections or suggestions have been received with regard to the aforesaid modifications ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this modification in the Gazette of India, namely :—

"Land use of plot No. 62, Block 'L', Dayanand Road, Daryaganj measuring about 303.5 Sq. Mts. (363 Sq. Yds.) falling in Zone A-20 (New Daryaganj) is proposed to be changed from 'residential' to 'commercial' (local shopping). The plot is surrounded by Dayanand Road in the North, residential area in in the South, plot No. 62-A in the east and Lekh Ram Road in the west."

[No. K-13012(3)/72-UDI(A)]

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1977

का० आ० 506.—यतः कतिपय उपान्तरण, जिन्हें केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में जोन डी-2 के लिए बृहत्त योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना में करने की प्रस्थापना करती है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसरण में, सूचना संख्या एफ०-3(53)/73-बृ० यो० दिनांक 22 मई, 1976 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित, प्रकाशित किए गए थे जिसमें आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्र के सम्बन्ध में आक्षेपों/सुझावों पर विचार करने के बाद बृहत्त योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय किया है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11(क) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली की बृहत्त योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना में, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित उपान्तरण करती है, अर्थात् :—

संशोधन :

"0 5 हेक्टेयर (1.25 एकड़) आकार क्षेत्रफल का, जो साधारणतया डा० सेन नार्सिंग होम के रूप में प्रसिद्ध है, तथा दिल्ली की बृहत्त योजना/क्षेत्रीय विकास योजना (जोन डी-2) में 'सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं/अस्पताल/नर्सिंग होम' के लिए निश्चित है और जो उत्तर में इन्स्टीट्यूशनल एरिया (चार्टर्ड एकाउन्टस संस्थान तथा इंजीनियर्स संस्थान), पूर्व में जोनल मार्ग/सर्विस लेन, दक्षिण में नाला/सर्विस रोड तथा पश्चिम में बहादुरशाह जफर मार्ग से घिरा हुआ है, वाणिज्यिक उपयोग (यूस जोन सी-2) में बदलने का प्रस्ताव है ।"

[सं० के-13011(6)/76-यू०डी०आई० (ए)]

डी० पी० ओहरी, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd February, 1977

S.O. 506.—Whereas certain modification, which the Central Government proposes to make in the Master Plan and the Zonal Development Plan for Zone D-2 regarding the area mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 3(53)/73-MP, dated the 22nd May 1976, in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) for inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act ;

And whereas the Central Government, after considering the objections/suggestions with regard to the area mentioned hereunder, has decided to modify the Master Plan and Zonal Development Plan ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the modification in the Master Plan and Zonal Development Plan with effect from the date of publication of the notification in the Gazette of India, namely :—

MODIFICATION:

"An area, measuring about 0.5 hect. (1.25 acres), commonly known as Dr. Sen Nursing Home, earmarked for 'public and semi-public facilities/hospital/nursing home' in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan (Zone D-2) and bounded by Institutional Area (Institute of Chartered Accountants and Institute of Engineers) in the north, zonal road/service lane in the east, nallah/service road in the south and Bahadurshah Zaffar Marg in the west, is proposed to be changed to 'commercial use' (use Zone C-2)."

[No. K-13011(6)/76-UDI(A)]

D. P. OHRI, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1977

का० आ० 507.—स्थाई आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने सूर्यपेठ टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-2-77 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-4/77-पी० एण्ड० बी०]

म० च० वर्मा, सहायक महानिदेशक (पी० एण्ड० बी०)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 28th January 1977

S O. 507.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627, dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-2-1977 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Suryapet Telephone Exchange, Andhra Circle.

[No. 5-4/77-PHB]

M. C. VERMA, Asstt. Dir. Genl. (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1977

का० आ० 508—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जैस्पर इंजीनियरिंग वर्क्स किशन गंज, हापुड़, जिला मेरठ, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(470)/76-पी० एफ०-2]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st January, 1977

S.O. 508.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Jasper Engineering Works, Kishan Ganj, Hapur, District Meerut, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1974.

[No. S. 35019 (470)/76-PF.II]

का० आ० 509—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् नौ सितम्बर, 1976 से सौसर विपनन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित, सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019(479)/76-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 509.— In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of September, 1976 the establishment known as Messrs. Sausar Vipnan Awam Prakriaya Sahakari Samiti Maryadit, Sausar, District Chhindwara (Madhya Pradesh), for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(479)/76-PF-II(ii)]

का० आ० 510—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एस० एस० बी० देव एण्ड कम्पनी, सी० आई० टी० रोड, स्कीम नं० 52, कलकत्ता-700014, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना एक जनवरी, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(20)/76-पी० एफ०-2]

S.O. 510.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. S.S.B. Deo and Company, C.I.T. Road, Scheme No. 52, Calcutta-700014, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1976.

[No. S. 35017(20)/76-PF-II]

का० आ० 511—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वुडेसाइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पुनकुन्नम, त्रिचुर-2, त्रिचुर ग्राम, त्रिचुर तालुक, त्रिचुर जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना एक दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(474)/76-पी० एफ०-2]

S.O. 511.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Woodesigns (Private) Limited, Poonkunnam, Trichur-2 Trichur village, Trichur Taluk, Trichur District, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1976.

[No. S 35019(474)/76-PF.II]

का० आ० 512—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक अगस्त, 1976 से कनारा रिट्रीडिंग एण्ड रबर वर्क्स, चिटपड़ी, उदिपि, दक्षिण कनारा नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019(478)/76-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 512.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of August, 1976 the establishment known as Messrs. Canara Retreading and Rubber Works, Chitpadi, Upidi, S. Kanara for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019 (478)/76-PF.II) (ii)]

का० आ० 513—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कनारा रिट्रीडिंग एण्ड रबर वर्क्स, चिटपड़ी, उदिपि, दक्षिण कनारा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना एक अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी

[सं० एस० 35019(478)/76-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 513.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Canara Retreading and Rubber Works, Chitpadi, Upidi, S. Kanara, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1976.

[No. S. 35019(478)/76-PF.II (i)]

का० आ० 514.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्काईलैण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, 123, सी० आर० एवेन्यू, कलकत्ता-700007 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना एक जून, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(18)/76-पी० एफ०-2(i)]

S.O 514.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Skyland Transport Company, 123, C.R. Avenue, Calcutta-700007 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1975.

[No. S. 35017(18)/76-PF.II(i)]

का० आ० 515—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक जून, 1975 से मैसर्स स्काईलैण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, 123, सी० आर० एवेन्यू, कलकत्ता-700007 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35017(18)/76-पी० एफ०-2]

S.O. 515.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of June, 1975, the establishment known as Messrs. Skyland Transport Company, 123, C.R. Avenue, Calcutta-700007 for the purposes of the said proviso.

[No. S-35017(18)/76-PF.II]

का० आ० 516.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, मैसर्स सदर्न एयर कण्डीशनिंग मैरीन सर्विस (प्राइवेट) लिमिटेड, 28/1 श्री मोहन लेन, कलकत्ता-700026 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना एक अगस्त, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017(21)/76-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 516.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Southern Air-conditioning Marine Service (Private) Limited, 28/4, Sree Mohan Lane, Calcutta-700026, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1975.

[No. S-35017(21)/76-PF. II(i)]

का० आ० 517.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक मार्च, 1975 से इन्टरकाफ्ट इण्डिया, 16-ए, नरायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019(477)/76—पी० एफ०-2]

S.O. 517.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the

Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of March, 1975 the establishment known as Messrs. Inter Craft India,, 16-A Naraina Industrial Area, Phase II, New Delhi, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(477)/76-PF II]

का०आ० 518 .—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक अगस्त, 1975 से साउदर्न ऐयर कण्डीशनिंग मैरीन सर्विस (प्राइवेट) लिमिटेड, 28/4, श्री मोहन लेन, कलकत्ता-26, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35017(21)/76-पी० एफ०-2]

S.O. 518.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of August, 1975 the establishment known as Messrs Southern Air-Conditioning Marine Service (Private) Limited, 28/4, Sree Mohan Lane, Calcutta 26, for the purposes of the said proviso

[No. S. 35017(21)/76-PF.II]

का०आ० 519 .—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केमिकल एजेंसी ग्राण्ड होटल बिल्डिंग, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019(465)/76-पी०एफ०-2(i)]

S.O. 519.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chemical Agency, Grand Hotel Building, Lal Darwaja, Ahmedabad-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1975.

[No. S. 35019(465)/76-PF.II(i)]

का०आ० 520 .—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 30 अप्रैल, 1975 से केमिकल एजेंसी, ग्राण्ड होटल बिल्डिंग, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-1 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019(465)/76-पी० एफ०-2]

S.O. 520.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of April, 1975 the establishment known as Messrs Chemical Agency, Grand Hotel Building, Lal Darwaja, Ahmedabad-1, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(465)/76-PF.II]

का०आ० 521 .—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सी० जी० आर० लिमिटेड, सान्ताक्रुज इलेक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, मरोल इण्डस्ट्रियल एरिया, अन्धेरी, मुम्बई-96 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना एक जनवरी, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम० 35018(73)/76-पी० एफ०-2]

S.O. 521.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs C. G. R. India Limited, Santa Cruz Eletronics Export Processing Zone, Marol Industrial Area, Andheri, Bombay-96, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1976.

[No. S. 35018(73)/76-PF.II]

का०आ० 522 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तकनीकी सेवा, 45-सरकारी औद्योगिक इस्टेट, कांदीवली, मुम्बई-67, जिसमें 778 खार, 5वीं सड़क, मुम्बई-52 स्थित इसका कार्यालय भी सम्मिलित है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(72)/76-पी० एफ०-2]

S.O. 522.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Technical Service, 45, Government Industrial Estate, Kandivali, Bombay-67 including its Office at 778, Khar 5th Road, Bombay-52, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1975.

[No. S 35018(72)/76-PF II]

का०आ० 523.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रेमन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, स्वामी विवेकानन्द रोड, गोरेगांव, मुम्बई-62 जिसमें अडवानी चैम्बर्स, पहली मंजिल, सर पी० एम० रोड, फोर्ट, मुम्बई-1 स्थित इसका कार्यालय शाखा भी सम्मिलित है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(74)/76-पी० एफ०-2]

S.O. 523.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Raymon Chemical Manufacturing Company, Swami Vivekanand Road, Goregaon, Bombay-62 including its branch office at Advani Chambers, Ist Floor, Sir P. M. Road, Fort, Bombay-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1976.

[No. S. 35018(74)/76-PF.II]

का०आ० 524.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1976 से मैसर्स वेजीटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, झरसुगुड़ा सम्बलपुर, उड़ीसा नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019(476)/76-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 524.—In exercise of the powers confered by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1976 the establishment known as Messrs Vegetable Products Limited, Jharsuguda, Sambalpur, Orissa, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(476)/76-PF.II(ii)]

का०आ० 525.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेजीटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, झरसुगुड़ा सम्बलपुर, उड़ीसा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019(476)/76-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 525.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vegetable Products Limited, Jharsuguda, Sambalpur, Orissa, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35019(476)/76-PF.II(i)]

का०आ० 526.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नाप्रो इण्डस्ट्रीज, घोड़बन्दर रोड, चितलसर-मानपाड़ा, पो० बॉक्स नं० 61, थाना-7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(71)/76-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 526.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Napro Industries, Ghodbunder Road, Chitalsar-Manpada, Post Box No. 61, Thana-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1975.

[No. S. 35018(71)/76-PF.II(i)]

का०आ० 527.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1975 से मैसर्स नाप्रो इण्डस्ट्रीज, घोड़बन्दर रोड, चितलसर-मानपाड़ा, पो० बाक्स सं० 61, थाना-7 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35018(71)/76-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 527.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1975 the establishment known as Messrs Napro Industries, Ghodbunder Road, Chitalsar-Manpada, Post Box No. 61-Thana-7, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(71)/76-PF.II(ii)]

का०आ० 528.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के

प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मार्च, 1976 से मैसर्स माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन एम्पलाइज को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सी० डी० बैरक, दुर्गापुर-10, जिला बर्दवान नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35017(15)/76-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 528.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty first day of March, 1976 the establishment known as Messrs Mining and Allied Machinery Corporation Employees' Cooperative Society Limited, C. D. Barrack, Durgapur-10 District Burdwan for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017(15)/76-PF. II(ii)]

का० आ० 529— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स आनन्दम सिनेमा, 76 राम मोहन बनर्जी रोड, कलकत्ता-35 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना एक जून, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35017(14)/76-पी० एफ० -2]

S.O. 529.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Anandam Cinema 67A, Ram Mohan Banerjee Road, Calcutta-35, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1975.

[No. S. 35017/14/76-PF.II]

का० आ० 530 — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स सर्वोदय अस्पताल, सरदार पटेल रोड, बालासिनोर, जिला केड़ा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना इकतीस अक्टूबर 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी

[सं० एस-35019(475)/76-पी० एफ०-2]

S.O. 530.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Sarvodaya Hospital, Sardar Patel Road, Balasinor, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notificcation shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1976.

[No. S. 35019(475)/76-PF.II]

का० आ० 531.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स शीतल टाकीज, नडियाड, जिला कैरा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019(459)/76-पी०एफ० 2]

S.O. 531.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shital Talkies, Nadiad, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1976.

[No. S-35019(459)/76-PF.II]

का० आ० 532.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स साबरडेयरी कर्मचारी सहकारी मंडली लिमिटेड, पो० बाक्स सं० 21 हिम्मतनगर, जिला साबरकांटा जिसमें (1) पब्लिक पार्क, हिम्मत नगर और (2) टावर रोड, हिम्मतनगर स्थित इसकी शाखाएं भी सम्मिलित है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019(464)/76-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 532.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sabardairy Karmachari Sahakari Mandli Limited, Post Box No. 21, Himatnagar, Sabarkantha District including its branches at (1) Public Park, Himatnagar and (2) Tower Road, Himatnagar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1976.

[No. S. 35019(464)/76-PF.II(i)]

का० आ० 533.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यमुना टाकिज, कापडवंज ताला कापडवंज जिला० कैरा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 मई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(458)/76-पी०एफ०2]

S.O. 533.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Yamuna Talkies, Kapadwanj, Tala, Kapadwanj, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of May, 1976.

[No. S. 35019/458/76 PF.II]

का० आ० 534.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज कांजीकोड पालघाट, केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(461)/76-पी०एफ०2]

S.O. 534.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Indian Telephone Industries, Kanjikode, Palghat, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1976.

[No. S. 35019/461/76-PF.II]

का० आ० 535.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अमर्सी ब्रादर्स (प्रोइवेट) लिमिटेड फेल्टहैम हाउस, ग्राहम रोड, बेलार्ड एस्टेट मुम्बई-1 (इसमे सोनेरी—महल भरोच स्थित इसकी शाखा भी सम्मिलित है) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35018(70)/76-पी०एफ०2]

S.O. 535.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Amersey Brothers (Private) Limited, Feltham House, Graham Road, Ballard Estate, Bombay-I, including its branch at Soneri Mahal, Broach, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1976.

[No. S. 35018(70)/76-PF.II]

का० आ० 536.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पी० एस० के० फाइनेन्स एण्ड चिट फन्डस कारपोरेशन, 395 बाजार स्ट्रीट सेलम, 1 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(456)/76-पी०एफ०2]

S.O. 536.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs P. S. K. Finance and Chit Funds Corporation, 395, Bazar Street, Salem-I, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35019(456)/76-PF.II]

का० आ० 537.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पन्चूर वाटर ट्रांसपोर्टस, दक्षिणी रेलवे के आउट एजेन्सी कन्ट्रैक्टर्स जेटी रोड, एलिप्पी केरल [इसमे विलिंगडन द्वारा (गुड्स शेड) कोचिन-3 स्थित इसकी शाखाएं भी सम्मिलित है] नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(412)/76-पी०एफ०2]

S.O. 537.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Punchur Water Transports, Out-Agency Contractors to the Southern Railway, Jetty Road, Alleppey, Kerala including its branch at Willingdon Island (Goodsheds) Cochin-3 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous

Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1976.

[No. S. 35019/412/76-PF.II]

का० आ० 538.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 30 जून, 1976 से साबरडेयरी कर्मचारी सहकारी मण्डली लिमिटेड पो० बाक्स सं० 21, हिम्मत नगर साबरकांठा जिला जिसमें (1) पब्लिक पार्क, हिम्मतनगर और टावर रोड, हिम्मत नगर स्थित इसकी शाखाएं भी सम्मिलित हैं, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 35019(464)/76-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 538.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of June, 1976 the establishment known as Messrs. Sarbardairy Karmachari Sahakari Mandli Limited, Post Box No. 21, Himatnagar, Sabarkantha District including its branches at (1) Public Park, Himatnagar and (2) Tower Road, Himatnagar for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(464)/76-PF.II(ii)]

का० आ० 539.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 अक्टूबर, 1976 से नन्दा कार्डामाम प्लाण्टेशन कूटामुंडा, कुन्नेमबेट्टा, डाकखाना एस० वेनाड कोजीकोड जिला नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019 (462)/76-पी० एफ०-2]

S.O. 539.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty first day of October, 1976 the establishment known as Messrs Nanda Cardamom Plantation, Kootamunda, Kunnembetta, Post Office S. Waynad Taluk, Kozhikode District, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(462)/76-PF.II]

का० आ० 540.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नन्दा कार्डामम प्लान्टेशन कूटामुंडा, कुन्नेमबेट्टा, डाकखाना एस० वेनाड ताल्लुक कोजीकोड जिला, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 अक्टूबर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०35019(462)/76-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 540.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nanda Cardamom Plantation, Kootamunda, Kunnembetta, Post Office S. Waynad Taluk, Kozhikode District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1976.

[No. S. 35019(462)/76-PF.II(i)]

का० आ० 541.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भासकर बाईडिंग वर्क्स, डी० एस० लेन, मामुलपेट, बंगलौर-53, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना इकतीस अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(471)/76-पी०एफ०-2]

S.O. 541.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bhaskar Binding Works, D-S-Lane, Mamulpet, Bangalore-53, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of August, 1976.

[No. S. 35019(47)/76-PF.II]

का० आ० 542.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अब्दुल करीम ऐण्ड संस, करीम बिल्डिंग्स नं० 729, चिकपेट, पोस्ट बाक्स नं० 7918, बंगलौर-53, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

यह अधिसूचना इकतीस जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(472)/76-पी० एफ-2]

S.O. 542.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Abdul Cureem and Sons, Cureem Buildings, No. 729, Chickpet Post Box No. 7918, Bangalore-53 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on thirty first day of July, 1976.

[No. S. 35019/472/76-PF. II]

का० आ० 543—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स कथोलिक प्रेस ऐण्ड बुक डिपो, कुविलौनि-13, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (473)/76-पी० एफ-2]

S.O. 543.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment know as Messrs Catholic Press and Book Depot, Quilon-13, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establshment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1976.

[No. S. 35019(473)/76-PF. II]

का० आ० 544—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स मालनाद कालिज आफ इंजीनियरिंग होस्टेल, हस्सान, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (466)/76-पी० एफ-2]

S.O. 544.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Malnad College of Engineering Hostel, Hassan, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicate to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1976.

[No. S. 35019(466)/76-PF. II]

का० आ० 545.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स कुमार सिल्क हाउस, सन्नाधी स्ट्रीट, थिरु, वुवानम, कुम्बाकोनम तालुक, जिला थनजावुर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक जनवरी, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (463)/76-पी० एफ-2]

S.O. 545.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kumar Silk House, Sennadhi Street, Thirbuvannam, Kumbakonam Taluk, Thanjavur District, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1976.

[No. S. 35019(463)/76-PF. II]

का० आ० 546.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स माईनिंग एण्ड एलाएड मशीनरी कारपोरेशन एम्पलाइज को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सी० डी० बैरक, दुर्गापुर-10, जिला बर्दवान' नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35017(15)/76-पी० एफ-2(i)]

S.O 546.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mining and Allied Machinery Corporation Employees' Cooperative Credit Society Limited, C. D. Barrack, Durgapur-10, District Burdwan have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1976.

[No. S. 35017(15)/76-PF. II]

का० आ० 547.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में

आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक जुलाई, 1969 से खेमका ऐविएशन (प्राइवेट) लिमिटेड, स्पीड बर्ड हाउस, एम ब्लाक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019 (469)/76-पी० एफ-2(ii)]

S.O. 547.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of July, 1969 the establishment known as Messrs Khemka Aviation (Private) Limited, speed Bird House, M-Block, Connaught Circus, New Delhi, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(469)/76-PF. II(ii)]

का० आ० 548.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स खेमका ऐविऐशन (प्राइवेट) लिमिटेड, स्पीड बर्ड हाउस, एम ब्लाक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक जुलाई, 1969 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(469)/76-पी० एफ-2(i)]

S.O. 548.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Khemka Aviation (Private) Limited, Speed Bird House, M-Block, Connaught Circus, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1969.

[No. S. 35019/469/76-PF. II(i)]

का० आ० 549.—अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स बंगाल इलेक्ट्रिकल्स कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, सं० 1, कुमार पार्क ईस्ट बंगलौर-1, जिसमें (1) खं1, थानिवाचालम चेटी रोड, टी, मद्रास-17 और (2)तानसुक टी० सी० नं० 19-247/बी, थाइकन्द त्रिवेन्द्रम स्थित उसकी शाखाएं भी सम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक अक्तूबर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (468)/76-पी० एफ-2]

S.O. 549.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relaion to the establishment known as Messrs Bengal Electricals Company (Private) Limited, No. 1, Kumara Park East, Bangalore-1, including its branches (1) B-1, Thanikachalam Chetty Road, T' Nagar, Madras-17 and (2) Tansuk, T.C. No. 19-247/B, Thycaud, Trivandrum, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act, to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1976.

[No. S. 35019(468)/76-PF. II]

का० आ० 550—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स इन्टरक्राफ्ट इण्डिया, 16-ए नरायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज 2 नई दिल्ली, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना एक मार्च, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (477)/76-पी० एफ-2(i)]

S.O. 550.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Intercraft India, 16-A, Naraina Industrial Area, Phase II, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1975.

[No. S. 35019(477)/76-PF. II (i)]

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1977

का० आ० 551.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 843, तारीख 2 फरवरी, 1976 और सं० का० आ० 2059 तारीख 31 मई, 1976 के अनुक्रम में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान से सम्बद्ध (1) नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली और (2) केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 23 अक्तूबर, 1976, 22 अक्तूबर, 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित है, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी —

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ, या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है, या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहिया और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं, या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा-बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि कारखाने को छूट देने के लिए महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिफारिश देर से प्राप्त हुई थी। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को आरम्भ में छूट दी गई थी वे अभी भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट का पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस०-38017/ /76-एच० आई०]

New Delhi, the 25th January, 1977

S.O. 551.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notifications of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 843 dated the 2nd February, 1976 and No S.O. 2059 dated the 31st May, 1976, the Central Government hereby exempts (1) the National Physical Laboratory, New Delhi and (2) Central Road Research Institute, New Delhi, belonging to the Council of Scientific and Industrial Research from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 23rd October, 1976 upto and inclusive of the 22nd October, 1977.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purpose of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory,

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the D.G., ESIC for the grant of exemption to the factory was received late. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not effect the interest of anybody adversely.

[No. S 38017/2/76-HI.]

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1977

का० आ० 552.—यतः मेसर्स नागपाल पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड मद्रास-600069 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छूट देने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार की राय में अभिदाय की दरों की बाबत उक्त स्थापन के भविष्य निधि नियम उसके कर्मचारियों के लिए उन नियमों से कम अनुकूल नहीं है जो उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट हैं, और कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रसुविधाओं का भी उपभोग कर रहे हैं जो उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल नहीं हैं, जो, उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों के संबंध में, उक्त अधिनियम के अधीन और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उपबंधित है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खंण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन से सम्बद्ध नियोजक, निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार का प्रत्येक मास के अंत के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे।

2. उक्त स्थापन से सम्बद्ध नियोजक—

(1) भविष्य निधि अभिदायों के विनिधान की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करेगा ;

(2) यह ध्यान रखने के लिए सम्यक् सावधानी बरतेगा कि उक्त स्थापन की बाबत गठित न्यासी बोर्ड भविष्य निधि/अभिदायों का विनिधान समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार करता है और उक्त न्यासी बोर्ड द्वारा भविष्य निधि अभिदायों के विनिधान के लिए उत्तरदायी ;

3. नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

4. नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण या पास बुक भेजेगा।

5. निधि के प्रशासन, जिसमें लेखाओं का बनाए रखना, लेखाओं और विवरणियों का भेजा जाना, संचयों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों आदि का संदाय सम्मिलित है, में होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

6. नियोजक प्रति वर्ष हर एक सदस्य के खाते में ऐसी दर पर जो न्यासी बोर्ड अवधारित करे ब्याज जमा करेगा और ऐसी दर उस दर से कम नहीं होगी जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए।

7 नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि के नियमों की एक प्रति स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और जब कभी उनमें संशोधन किया जाएगा तब कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद भी प्रदर्शित करेगा।

8. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी निधि) या छूट प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही से सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित होता है तो नियोजक स्थापन की निधि के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त ही दर्ज करेगा और ऐसे कर्मचारी की बाबत उसके पिछले संचयों को स्वीकार करके उन्हें उसके खाते में जमा करेगा।

9 यदि उस वर्ग के स्थापनों के लिए, जिसमें नियोजक का स्थान आता भविष्य निधि के अभिदायों की दर उक्त अधिनियम के अधीन बढ़ा जाए तो नियोजक भविष्य निधि के अभिदायों की दर समुचित रूप से बढ़ा देगा ताकि स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन की प्रसुविधाएं उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल न हो जाएं जिनकी व्यवस्था उक्त अधिनियम के अधीन है।

10. स्थापन अपने भविष्य निधि का संपरीक्षित तुलनापत्र हर वर्ष प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त को वर्षान्त के तीन मास के भीतर भेजेगा।

11. स्थापन के भविष्य निधि नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सदस्य को उस स्थापन का कर्मचारी न रह जाने की दशा में देय रकम अथवा किसी अन्य स्थापन को उसका स्थानान्तरण हो जाने पर अन्तरणीय रकम जो कि नियोजक और कर्मचारियों के अभिदाय के रूप तथा उस पर ब्याज और उसके अतिरिक्त वह रकम भी, यदि कोई हो, जो उपदान या पेंशन नियमों के अधीन देय है, कुल मिलाकर यदि उस रकम से कम है जो नियोजक और कर्मचारी के अभिदाय के रूप में तथा उस पर ब्याज के रूप में उस दशा में देय होती जब कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अधीन भविष्य निधि का सदस्य होता, तो नियोजक इन रकमों के अन्तर के बराबर रकम सदस्य को क्षतिपूर्ति के रूप में अथवा विशेष अभिदाय के रूप में संदत्त करेगा।

12. भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अनुमोदित करने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

[सं० 35014(25)/76-पी० एफ०]

New Delhi, 27th January, 1977

S.O. 552.—Whereas Messrs. Nagpal Petro-Chemical Limited, Manali, Madras-600069 (herein after referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952);

And, whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees therein then those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees then the benefits provided under the said Act or under the Employees Provident Funds Scheme, 1952 (herein-after referred to as the said scheme) in relation the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), within 15 days from the close of every month.

2 The employer in relation to the said establishment—

(i) shall comply with the direction issued by the Central Government, from time to time, under clause (a) of sub section (3) of section 17 of the said Act in regard to the investment of provident fund contributions, and

(ii) shall take due care to see that the Board of Trustees constituted in respect of that establishment invest the provident fund contributions in accordance with the directions issued by the Central Government from time to time, and shall be responsible for such investment of the provident fund contributions by the said Board of Trustees

3 The employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government may, from time to time, direct

4 The employer shall furnish to each employees an annual statement of account or Pass Book

5 All expenses involved in the administration of the fund including the maintenance of accounts submission of accounts and returns, transfer of accumulations, payment of inspection charges, etc , shall be borne by the employer

6 The employer shall credit, every year to the account of each member interest at such rates as may be determined by the Board of Trustees, and such rate shall not be less than the one determined by the Central Government from time to time

7 The employer shall display on the notice board of the establishment a copy of the rules of the fund as approved by the appropria e Government and, as when amended, alongwith a translation of the salient and points thereof in the language of the majority of the employees

8 Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory Fund) or the provi dent fund of another exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of he fund of the establishment, and accept the past accumulations in respect of such employee and credit to his account

9 The employer shall enhance the rate of provident fund contribution appropriately if the rate of provident fund con tributions for the class of establishments in which this es tablishment falls is enhanced under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) so that the benefits under the provident fund scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefit provided under the said Act

10 The establishment shall submit an audited bal nce sheet of its provident fund every year to the Regional Com missioner within three months of the close of the year

11 Notwithstarding anything contained in the rules to of the provident fund of the establishment if the amount pay able to any member, upon his ceasing to be an employee of the establishment or transferable on his transfer to any other establishment, by way of employers and employees' contributions plus interest thereon taken together with the amount if any, payable under he Gratuity or Pension Rules be less than the amount that would be payable as employer's and employees' contributions plus interest thereon, if he were member of the Provident Fund under the Employees' Provi dent Fund Scheme, 1952, the employer shall pay the diffe rence to the member as compensation or special contribution

12 No amendment of the rules of the provident fund of the establishment shall be made without the previous appro val of the Regional Provident Fund Commissioner and where any amendment is likely to effect adversely the interests of the employees the Regional Provident Fund Commissioner Madras shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

[No S 35014(25)/76 PF II]

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1977

का० आ० 553—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और नियोजन विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3073 तारीख 19 अक्तूबर, 1973 को, जहां तक इसका सम्बन्ध श्री कृष्ण लाल बनर्जी से है, विखण्डित करती है।

[सं० ए० 12016(1)/76-पी० एफ० 1]

New Delhi, the 28th January, 1977

S.O. 553.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment No S O 3073 dated the 19th October 1973 in so far as it relates to Shri Krishna Lal Banerjee

[No A-12016(1)/76 PF I]

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1977

शुद्धि पत्र

का० आ० 554—भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 14 अगस्त, 1976 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2979, तारीख 26 जुलाई, 1976 में पृष्ठ 2759 पर पैरा 1 में पंक्ति 3 और 4 में "राष्ट्रीय प्रयोगशाला, पुणे" के स्थान पर "राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे" पढ़ें।

[सं० एस०-38014/21/76-एच० आई०]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th January, 1977

S.O. 554.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No S O 2879, dated the 26th July, 1976, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub section (ii) dated the 14th August 1976 at page 2759 in paragraph 1, in lines 3 and 4, for "National Laboratory, Poona", read "National Chemical Laboratory Poona"

[No S-38014/21/76-HI]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

का० आ० 555—लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, पाईकरोकल्म गार्डन रोड, मद्रास-600006, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन छूट देने के लिये आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार की राय में अभिदाय की दरों की बाबत उक्त स्थापन के भविष्य निधि नियम उसके कर्मचारियों के लिये उन नियमों से कम अनुकूल नहीं हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट हैं, और कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रसुविधाओं का भी उपभोग कर रहे हैं जो उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल नहीं है जो उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम के अधीन

और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उपबन्धित है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन से सम्बद्ध नियोजक, निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा और प्रत्येक मास के अन्त के 15 दिन के भीतर संदेय निरीक्षण प्रभार का संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे।

2. उक्त स्थापन से सम्बद्ध नियोजक—

(1) भविष्य निधि अभिदायों के विनिधान की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों का पालन करेगा,

(2) यह ध्यान रखने के लिये सम्यक् सावधानी बरतेगा कि उक्त स्थापन की बाबत गठित न्यासी बोर्ड भविष्य निधि अभिदायों का विनिधान समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार करता है और उक्त न्यासी बोर्ड द्वारा भविष्य निधि अभिदायों के विनिधान के लिये उत्तरदायी होगा;

3. नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

4. नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण या पास बुक भेजेगा।

5. निधि के प्रशासन, जिसमें लेखाओं का अनायें रखना, लेखाओं और विवरणियों का भेजा जाना, संचयों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों आदि का संदाय सम्मिलित है, में होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

6. नियोजक प्रति वर्ष हर एक सदस्य के खाते में ऐसी दर पर जो न्यासी बोर्ड अवधारित करे ब्याज जमा कर देगा और ऐसी दर उस दर से कम नहीं होगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाये।

7. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि के नियमों की एक प्रति स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और जब कभी उनमें संशोधन किया जायेगा तब कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद भी प्रदर्शित करेगा।

8 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी निधि) या छूट प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही से सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित होता है तो नियोजक स्थापन की निधि के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त ही दर्ज करेगा और ऐसे कर्मचारी की बाबत उसके पिछले संचयों को स्वीकार करके उन्हें उसके खाते में जमा करेगा।

9. यदि उस वर्ग के स्थापनों के लिये, जिसमें नियोजक का स्थान आता भविष्य निधि के अभिदायों की दर उक्त अधिनियम के अधीन बढ़ा दी जाये तो नियोजक भविष्य निधि के अभिदायों की दर समुचित रूप से बढ़ा देगा ताकि स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन की प्रसुविधायें उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल न हो जायें जिनकी व्यवस्था उक्त अधिनियम के अधीन है।

10. स्थापन अपने भविष्य निधि का संपरीक्षित तुलनपत्र हर वर्ष प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त को वर्षान्त के तीन मास के भीतर भेजेगा।

11. स्थापन के भविष्य निधि नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सदस्य को उस स्थापन का कर्मचारी न रह जाने की दशा में देय रकम अथवा किसी अन्य स्थापन को उसका स्थानान्तरण हो जाने पर अन्तरणीय रकम जो कि नियोजक और कर्मचारियों के अभिदाय के रूप तथा उस पर ब्याज और उसके अतिरिक्त वह रकम भी, यदि कोई हो, जो उपदान या पेंशन नियमों के अधीन देय है, कुल मिलाकर यदि उस रकम से कम है जो नियोजक और कर्मचारी के अभिदाय के रूप में तथा उस पर ब्याज के रूप में उस दशा में देय होती जब कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अधीन भविष्य निधि का सदस्य होता, तो नियोजक इन रकमों के अन्तर के बराबर रकम सदस्य को क्षतिपूर्ति के रूप में अथवा विशेष अभिदाय के रूप में सदत्त करेगा।

12. भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अनुमोदन करने से पूर्व, कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

[सं० 35014/34/76-पी०एफ० 2]

एम० एस० महालिंगम, उप सचिव

New Delhi, the 29th January, 1977

S.O. 555.—Whereas Messrs The Lakshmi Vilas Bank Limited 1, Pycrofts Garden Road, Madras-600006, (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) ;

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 of the said Act, and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Povident Funds scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the Employees in any other establishment of a similar character :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (2) of sub-section (1) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Funds Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), the inspection charges being payable within 15 days from the close of every month.

2. The employer in relation to the said establishment :—

(i) shall comply with the directions issued by the Central Government, from time to time, under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the said Act in regard to the investment of Provident Fund contributions; and

(ii) shall take due care to see that the Board of trustees constituted in respect of that establishment invest the provident fund contributions in accordance with the directions issued by the Central Government, from time to time, and shall be responsible for such investment of the provident fund contributions by the said Board of trustees.

3. The employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government may from time to time, direct.

4. The employer shall furnish to each employee an annual statement of account or Pass Book.

5. All expenses involved in the administration of the Provident fund including the maintenance of accounts, submission of accounts and returns, transfer of accumulations, payment of inspection charges, etc., shall be borne by the employer.

6. The employer shall credit, every year to the account of each member interest such rates as may be determined by the Board of trustees, and such rate shall not be less than the one determined by the Central Government from time to time.

7. The employer shall display on the Notice board of the establishment a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

8. Where an employee who is already member of the Employees Provident Fund (Statutory Fund) or the provident fund of another exempted establishment is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the provident fund of the establishment, and accept the past accumulations in respect of such employee and credit to his account

9. The employer shall enhance the rate of provident fund contribution appropriately if the rate of provident fund contributions for the class of establishments in which his establishment falls is enhanced under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) so that the benefits under the provident fund scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefit provided under the said Act.

10. The establishment shall sumbit an audited balance sheet of its provident fund every year to the Regional Commissioner within three months of the close of the year.

11. Notwithstanding anything contained in the provident fund rules of the establishment, if the amount payable to any member, upon his ceasing to be an employee of the establishment or transferable on his transfer to any other establishment, by way of employers' and employees' contributions plus interest thereon taken together with the amount, if any, payable under the Gratuity or Pension Rules, be less than the amount that would be payable as employer's and employees' contributions plus interest thereon, if he were a member of the Provident Fund under the employee's Provident Funds Scheme, 1952, the employer shall pay the difference to the member as Compensation or Special Contribution.

12. No amendment of the rules of the provident fund shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees in the establishment, the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees' to explain their point of view.

[No. S. 35014/34/76-PF. II]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1976

का० आ० 556.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मद्रास स्टेवेडोर्स एसोसिएशन मद्रास के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० एन० सिंगारवेलु होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मद्रास स्टेवेडोर्स एसोसिएशन, मद्रास का श्री एम० कुप्पुस्वामी, चौकीदार की सेवाओं को 24 मार्च, 1976 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल० 33012(4)/76-डी-4(ए)]

ORDER

New Delhi, the 23rd December, 1976

S O.556.—Whereas the Central Government is of opinion that an Industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Madras Stevedores Association, Madras and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. N. Singaravelu shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the Madras Stevedodes Association, Madras is justified in terminating the services of Shri M. Kuppuswamy, Watchman, with effect from the 24th March, 1976 ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

[No. 33012(4)/76-D. IV(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1976

का० आ० 557—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स विजय शिपिंग एंड क्लीयरिंग हाउस, कोचीन-682001 के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० एन० सिंगारवेलु होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा, और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स विजय शिपिंग एंड क्लीयरिंग हाउस, कोचीन के प्रबन्धतन्त्र की अपने सहायक, श्री आर० कृष्ण पाई को 24 फरवरी, 1976 से पदच्युत

करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल-35012(2)/76-डी० 4(ए)]

नन्द लाल, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 24th December, 1976

S.O. 557.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Vijaya Shipping and Clearing House, Cochin-682001 and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. N. Singaravelu shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Vijaya Shipping and Clearing House, Cochin in dismissing Shri R. Krishna Pai, their Assistant, from the 24th February, 1976 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

[No. L-35012(2)/76-D. IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer.

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

का० आ० 558.—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची के प्रथम भाग में ग्रेफाइट खानों में नियोजन जोड़ती है, और ऐसा करने के अपने आशय की सूचना भारत के राजपत्र, तारीख 10 जुलाई, 1976 के पृष्ठ 2475 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2491 द्वारा पहले ही दे चुकी है।

[सं० एस० 32017/1/73-डब्ल्यू० ई० (एम० डब्ल्यू०)]

टी० एस० शंकरन, अवर सचिव

New Delhi, the 29th January, 1977

S.O. 558.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) the Central Government hereby adds to Part I of the Schedule to that Act the employment in Graphite Mines, notice of its intention to do so having already been given by the notification of Government of India in the Ministry of Labour No S.O. 2491 dated the 22nd June, 1976 published at page 2475 of the Official Gazette dated the 10th July, 1976.

[No. S-32017/1/73-WE(MW)]

T. S. SANKARAN, Addl. Secy.

New Delhi, the 18th January, 1977

S.O. 559.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the Ramagundam Division I of Singareni Collieries Company Ltd., P. O. Godavari Khani (Andhra Pradesh) and their workmen which was received by the Central Government on the 17th January, 1977.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 1 of 1972

BETWEEN

Workmen of Ramagundam Division I of Singareni Collieries Company Limited, (P.O.) Godavari Khani, Andhra Pradesh.

AND

The Management of Ramagundam Division I of Singareni Collieries Company Limited, (P.O.) Godavari Khani, Andhra Pradesh.

APPEARANCES :

(1) Sri A. Lakshmana Rao, Advocate—for Workmen.

(2) Sri D. Gopala Rao, Advocate—for Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) through its order No. L/2112/27/71-LR. II dated 29-12-1971 referred under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 the following dispute existing between the Management of Ramagundam Division I of Singareni Collieries Company Limited, Post Office Godavari Khani, Andhra Pradesh and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Is the management of Ramagundam Division-I of Singareni Collieries Company Limited justified in not giving Category V wages with effect from the 15th August, 1967, to Sarvasri Shaik Nayamad, V. Venkat Raj, S. Laxminarain, Vishnumurthy and Mydari Rayamallu, Moulders in Workshop as per recommendations of the Wage Board for Coal Mining Industry and, if not, to what relief are the said workmen entitled and from what date ?"

2. The reference was registered as Industrial Dispute No. 1 of 1972 and notices were issued to both the parties in response to which the workmen filed a claims statement and the Management also filed their counter.

3. One of my learned predecessors recorded the evidence of W.Ws 1 and 2 and M.W. 1 and marked Exs. W1 to W8 and M1 to M5 and passed an award dated 9-11-1972 holding that the present dispute was also covered by Industrial Dispute No. 30 of 1967 and that it would not be in the interests of the parties to give a decision thereon in the present dispute when Industrial Dispute No. 30 of 1967 was pending.

4. The workmen preferred Writ Petition No. 3973 of 1973 to the High Court of Andhra Pradesh, Hyderabad against the award passed by my learned predecessor. This Industrial Dispute relates to 5 Moulders. There was another Industrial Dispute pending in Industrial Dispute No. 87 of 1971 relating to 27 khalasis. In both these Industrial Disputes a similar award was passed by my learned predecessor stating that the dispute could not be decided in view of the pendency of Industrial Dispute No. 30 of 1967. The workmen who were parties to Industrial Dispute No. 87 of 1971 preferred Writ Petition No. 3976 of 1973 against the award passed therein. Industrial Dispute No 30 of 1967 was subsequently disposed and an award was passed in it. Both the above Writ Petitions were disposed of by the High Court through its Judgment dated 18-7-1975. The High Court was pleased to set aside the award passed by this Tribunal and remitted the matter back to this Tribunal for passing a consequential award pursuant to the award in Industrial Dispute No. 30 of 1967 subject to a decision on the question of identity of the Khalasis and Moulders.

5. On 5-11-1976 a memo was filed on behalf of the workmen stating that the dispute had been settled out of Court, that the workmen had given up their demands and did not press the same. It was further mentioned in the memo that it was not necessary to consider the evidence on record and that a nil award might be passed The Management has no objection to this course.

6 When the workmen choose not to press their demands and give them up on account of the settlement reached out of Court the demands must be taken to be waived and there is no need either to consider the evidence or to adjudicate upon the claims put forward

A Nil Award is hereby passed

Dictated to the Stenographer transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal this the 22nd day of November, 1976

K P NARAYANA RAO, Presiding Officer

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses Examined For Workmen	Witness Examined For Employers
WW 1 Shaikh Niyamat	MW 1 A Satyanarayana
WW 2 Binvarilal	

Documents Exhibited for Workmen

Ex W1 Authorisation of Tradesmen (moulding) dt 29-9-66 issued by the Manager Gdk No 2 incline in respect of S Niyamat

Ex W2 True Copy of the authorisation of Tradesman (moulding) dt 8 9 1966 issued by the Manager Gdk No 2 Incline in respect of Sri B Venkata Raju

Ex W3 True Copy of the Discharge Certificate dt 12-3 1965 issued by the Principal, Industrial Training Institute Kothagudem in respect of Sri B Venkata Raju

Ex W4 True Copy of the Provisional Certificate dt 3 3 65 issued by the Principal Industrial Training Institute Kothagudem in respect of Sri B Venkata Raju

Ex W5 True Copy of the Provisional Certificate dt 6-12-65 issued by the Principal, Industrial Training Institute Kothagudem in respect of Sri B Venkata Raju

Ex W6 True Copy of the Transfer Certificate Zilla Parishad High School Gudibanda Huzurnagar, Nalgonda Distt A P issued by the Head of the Institution in respect of B Venkata Raju

Ex W7 True Copy of the Circular of Singareni Collieries Company Limited Kothagudem dated 13-10 67 about implementation of the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry

Ex W8 True Copy of the Extracts Wage Schedule P No 8 of Singareni Collieries Company Limited, dt 27 7 1961

Documents Exhibited for Employers

Ex M1 Particulars of castings done from 1966 to 1967 in Godavari Khani Workshop

Ex M2 True Copy of the Minutes of Discussion held at Hyderabad on 11th & 12th February, 1966 between the representatives of the Management Singareni Collieries Company Limited and the Representative of the Workmen in the presence of the members of Wage Board for Coal Mining Industry regarding categorisation of the daily rated workers of Singareni Collieries Company Limited

Ex M3 Copy of the Memorandum of Settlement dt 5-11-1967 between the Management of Singareni Collieries Company Limited and the workmen represented by the A P Colliery Mazdoor Sangh in I D No 17 of 1966

Ex M4 Copy of the appointment Order as Industrial Training Institute Apprentice (moulder) issued by the General Manager, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Collieries in respect of Sri R Vishnumurthy

Ex M5 Copy of the (Appendix A) categorisation of Tradesmen in Ramagundam Divns I & II and (Appendix-B) Categorisation of workshops Gdk I & II Divisions etc, etc,

K P NARAYANA RAO, Presiding Officer

[No L 2112/27/71 LR II] & [No L 21025/3/75-D III B]

S O. 560.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ramagundam Divisions I & II of Singareni Collieries Company Ltd, P O Godavari Khani (A P) and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th January, 1977

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No 72 of 1971

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Co, Ltd, (P O) Godavari Khani, Ramagundam Division Nos I & II

AND

Management of Singareni Collieries Company Limited (P O) Godavari Khani Ramagundam Division Nos I & II

APPEARANCES

(1) Sri A Lakshmana Rao Advocate—for Workmen

(2) Sri D Gopala Rao Advocate—for Management

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation Department of Labour and Employment through its order No L/2112/29/71-LR II dated 19 10-1971 referred under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947 the following dispute existing between the Employers in relation to the Ramagundam Division Nos I & II of Singareni Collieries Company Limited, Post Office Godavari Khani, Andhra Pradesh and their workmen to this Tribunal for adjudication —

"Whether the management of Ramagundam Divisions I and II of Singareni Collieries Company Limited, is justified in designating the following 55 workmen as Fitter/Electrical Mazdoors and denying them wages of Electrical/Fitter Helpers? If not, to what relief are the workmen entitled and from what date?

1 Gollapalli Sathaiah,
2 N Rajam,
3 Kagithapu Chandraiah,
4 C L John,
5 Dubbasi Rajam,
6 Syed;
7 Muduthala Rajaiah
8 Jaknaboyina Kanakaiah,
9 Peradla Lingaiah;
10 B Rajalingam;
11 Ch Raja Reddy;
12 Bismilla Khan,
13 Md Raj Mohammad,
14 Neelam Venkat Rajam,
15 N Achaiah,
16 Chenigarapu Rayamallu,
17 Chinna Lingaiah,
18 Syed Pasha;
19 Bairam Laxminarayana,
20 M Rajaiah,
21 Prasada Rao,
22 Adepu Bheemaiah,
23 A Lazar,
24 D Ramaswamy,
25 M Ram Reddy,
26 M Joseph

27. N. Gangam Rajam;
28. Jainullabuddin;
29. T. Someshwar Rao;
30. Ch. Rajaiah;
31. T. Srisylam;
32. B. Radhakrishna Murthy;
33. Raheemuddin;
34. Poli Rajulingu;
35. Nagabhushanam;
36. Buchi Ramulu;
37. Venkateswaraiah;
38. Mallapalli Chandraiah;
39. Elupula Narsaiah;
40. G. Khagava;
41. E. Prakasham;
42. B. Suryanarayana;
43. Ganpathi Rao;
44. Jaffer Khan;
45. G. Ganpath;
46. V. Gopal Rao;
47. V. Chokka Rao;
48. Sk. Dawood;
49. Veeraswamy;
50. D. Gopal Rao;
51. K. Rajamallu;
52. M. Rajamallu;
53. M. Mallesham;
54. Goray Miya and
55. Raj Babu.—"

2. The reference was registered as Industrial Dispute No. 72 of 1971 and notices were issued to both the parties in response to which the workmen filed a claims statement and the Management also filed their reply statement.

3. One of my learned predecessors recorded the evidence of W.Ws. 1 to 9 and M. Ws. 1 to 4 and marked Exs. W1 and M1 and passed an award on 8-2-1973 holding that the Management was justified in designating the 55 workmen as Fitter/Electrical Mazdoors and that there was no question of denying to these workmen wages of Electrical/Fitter Helpers as the case may be, since there was no designation as Electrical/Fitter Helpers in Ramagundam Divisions I & II and that the workmen were not entitled to any relief.

4. Aggrieved by the said award the workmen preferred with Petition No. 4235 of 1973 to the High Court of Andhra Pradesh. The High Court by its judgment dated 3-9-1975 was pleased to set aside the award passed by my learned predecessor in so far as it relates to the second limb of the question referred in for adjudication, namely, whether the 55 workmen in question were denied the wages of Electrical/Fitter or Mechanical Fitter and the High Court remitted the matter back to this Tribunal to consider and adjudicate on the said question and pass the necessary award.

5. The workmen's contention was that the Management of Singareni Collieries Company Limited. Ramagundam Divisions I and II were improperly denying Category II wages to 55 workmen who were being employed as Fitter/Electrical Helpers but were being paid only Category I wages though they were actually doing the work of Helpers to either Fitters or Electricians and that in this manner the Management was exploiting the labour. The workmen put forth the above claim on the basis of the recommendations of the Wage Board for Mining Industries. The Management's contention was that the report of the Wage Board was only a recommendatory in character and that the proper authority to categorise and fix the wages was the employer. My learned predecessor held that there was no designation of Electrical and Fitter Helpers in Ramagundam though there was such a designation in the other mines at Kothagudam, Bellampally etc Now the matter is remitted back for passing an award in respect of the claim put forth by the workmen for wages as Electrical/Fitter Helpers

6. On 8-11-1976 a memo was filed on behalf of the workmen stating that this industrial dispute had been settled out of Court, that the workmen had given up the demands and did not press the same and that there was no need to consider the evidence on record. It was requested that a nil award might be passed The Management has no objection to this course.

7. Since the workmen have chosen not to press their demands even in respect of the wages on account of the settlement arrived at out of Court, there is no need to consider the evidence already recorded in this case. The demands must be deemed to have been given up by the workmen and as such the claim is hereby negatived.

A Nil Award is hereby passed.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 22nd day of November, 1976.

K. P. NARAYANA RAO, Presiding Officer

APPENDIX OF EVIDENCE :

Witnesses Examined For Workmen :	Witnesses Examined For Management :
W.W. 1 Sri D. Rajaiah	M.W 1 Sri R. K. Sinha.
W.W. 2 Sri T. Someswara Rao	M.W. 2 Sri M. Satyanarayana
W.W. 3 Sri Mohd. Wahad Ali.	M.W. 3 Sri M. A. Jabbar.
W.W. 4 Sri K. Krishna Murthy.	M.W. 4 Sri G. V. Krishna
W.W. 5 Sri G. Limbadri.	Rao
W.W. 6 Sri M. Sudersanam.	
W.W. 7 Sri D. Pratap Reddy	
W.W. 8 Sri C. P. Ramalingam.	
W.W. 9 Sri Bangaru Sayulu.	

Documents marked on behalf of Workmen :

Ex. W1 Memo dated 18-5-72 issued by the Manager, G.D.K. I Incline to Dubasi Rajam, Fitter Mazdoor.

Documents marked on behalf of Management :

Ex. M1 List showing the category I Mazdoors of G.D.K. No. I Incline.

K. P. NARAYANA RAO, Presiding Officer

[No. L-21025/1/76-D III B & L-2112]

S.O. 561.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Ltd., Ramagundam Divisions I & II and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th January, 1977.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 87 of 1971

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Divisions I & II.

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Divisions I & II

APPEARANCES :

(1) Sri A. Lakshmana Rao, Advocate—for Workman.
(2) Sri D Gopala Rao, Advocate—for Management

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment through its order No L/2112/32/71-LR II dated 3-12-1971 referred

under Section 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 the following disputes existing between the Management of Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudam Collieries, Andhra Pradesh and their workmen to this Tribunal for adjudication :—

"1. Is the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudam (Ramagundam Divisions I and II) justified in employing Sarvasri Raja Moinuddin, Morugu Cattaiah, Bahdur Khan, Sardar Khan, D. Srihar, Md. Gaffar, Kunta Parvathalu, Elgam Rajam, Soula Laxmaiah, M. Iswari Das, Y. Hanumanth Rao, Sardar Khan, Matta Kistaiah, Kedari Mallaiah, R. Bhadraiah, E. Venkati, K. Mallaiah, Sk. Yacoob Ali and A. Durgaiah, Category III Pump Khalasis on more than one pump during the week from the 23rd May, 1971 to the 29th May, 1971 and in refusing to pay them category IV wages for the said period ? If not justified, to what relief are the said workmen entitled for the said period and also for the periods when they were employed on more than one pump ?"

"2. Is the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudam (Ramagundam I and II Divisions) justified in employing Sarvasri D. Radhakrishna, Kannam Rajanarsu, Kondalaxman, Dasi Posham, Janga Ch. Posham, Thatikonda Rajesham, Nimmala Ramaswamy, K. Venkaty, Oddy Rayamallu and Kamuni Odalu, Category-II Pumps Khalasis on more than 35 H.P. Pumps during the week from the 23rd May, 1971 to the 29th May, 1971 and in refusing to pay them category-III wages for the said period ? If not justified, to what relief are the said workmen entitled for the said period and also for the periods when they were employed on more than one pump ?"

"3. Is the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudam (Ramagundam I and II Divisions) justified in employing Sarvashri Purandla Ramulu, A. Verraswamy, D. Rajamouli, Raja Mohammad, J. Samuel, S. Suryanarayana, Ghousuddin, Maddela Durgaiah, L. Venkaty, G. Ramallu, Erabathula Muthaiah, Kendukuri Agaiah and Elupula Ramula, Category-II Pump Khalasis on more than one pump and also on more than 35 H.P. Pumps during the week ending 23rd May, 1971 to the 29th May, 1971 and in refusing to pay them Category IV wages ? If not justified, to what relief are the said workmen entitled for the said period and also for the periods when they were employed on more than one pump ?"

2. The reference was registered as Industrial Dispute No. 87 of 1971 and notices were issued to both the parties in response to which the workmen filed a claims statement and a counter was also filed by the Management.

3. One of my learned predecessors recorded the evidence of W. Ws 1 to 7 and M.Ws 1 to 4 and marked Exs. W1, M1 and M2 and passed an award dated 28-12-1972 holding that the Claimants were not entitled to any relief because the question whether the action of the Management in not giving them higher category wages was justified or not was pending consideration in Industrial Dispute No. 30 of 1967.

4. Another industrial dispute in Industrial Dispute No. 1 of 1972 was also pending in this Tribunal and it related to the fixation of 5 Moulders into category No. 5 for the purposes of wages. The present Industrial Dispute relates to 27 Khalasis. In both these matters my learned predecessor passed an award stating that no final award could be passed in view of the pendency of Industrial Dispute No. 30 of 1967 wherein identical questions arose for determination. The workmen preferred Writ Petition No. 3973 of 1973 against the award in Industrial Dispute No. 1 of 1972 and Writ Petition No. 3976 of 1973 against the award in this Industrial Dispute. Industrial Dispute No. 30 of 1967 was disposed of and an award was passed in it. Thereafter the High Court allowed both the aforesaid Writ Petitions on 18-7-1975 and remitted both the matters to this Tribunal with a direction to pass a consequential award pursuant to the award made in Industrial Dispute No. 30 of 1967 subject to the determination of certain other questions.

5. On 5-11-1976 a memo was filed on behalf of the workmen stating that the matter had been settled out of Court, that the workmen had given up the demands and did not press the same. It was further mentioned in the memo that it was not necessary to consider any evidence on record and that a nil award might be passed. The management has no objection to this course.

6. In view of the aforesaid memo it has to be held that the workmen do not press their demands and give them up on account of a settlement reached out of Court. When the workmen give up their demands there is no need to consider the evidence and pass a fresh award.

A Nil Award is hereby passed.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 22nd day of November, 1976.

K. P. NARAYANA RAO, Presiding Officer

APPENDIX OF EVIDENCE :

Witnesses Examined For Workmen :	Witnesses Examined For Employers :
W.W. 1 P. Ramulu.	M.W. 1 M. Satyanarayana.
W.W. 2 M. Eshwar Das.	M.W. 2 Sukhlal.
W.W. 3 D Sectaramaiah.	M.W. 3 Gangadhar Vanam.
W.W. 4 Sheikh Yakoob Ali.	M.W. 4 M. A. Jabbar.
W.W. 5 M. Devadatham.	
W.W. 6 A. Papaiah.	
W.W. 7 Das Posham.	

Documents Exhibited for Workmen :

Ex. W1 Copy of the letter dt. 23-5-70 of Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Dept. of Labour & Employment) New Delhi addressed to the Labour Relations Advisor, Associated Cement Companies Limited, Bombay.

Documents Exhibited for Employers :

Ex. M1 Copy of the letter dt. 21-4-69 of Government of India, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation, Department of Labour & Employment, New Delhi, addressed to the Agent, Singareni Collieries Company Ltd., Bellampalli and the Vice President, S. C. Workers Union, Bellampalli.

Ex. M2 Copy of the letter dt. 1-7-68 of the Secretary of India Mines Association, Calcutta addressed to the General Manager, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.

K. P. NARAYANA RAO, Presiding Officer

[No. L-21025/3/75-DO III B]

New Delhi, the 29th January, 1977

S.O. 562.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Rajasthan, Jaipur, in the industrial dispute between the employers in relations to the management of Bagalia Sand Stone Mines in the District of Bundi (Rajasthan) of Shri Hiralal Mewara, Mewara Stone Co. Kottari Chouraha, Kota and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th January, 1977.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, RAJASTHAN, JAIPUR.

Case No CIT-10 of 1976.

REFERENCE

Government of India, Ministry of Labour, Notification No. L-29011/11/76-D. III(B), dated 7th June, 1976.

In the matter of Industrial Dispute :

BETWEEN

Patthar Khan Majdoor Sangh, Kota.

AND

Shri Hiralal Mewara through Mewar Stone Co., Kota.

APPEARANCE :

None.

AWARD

By its notification dated 7-6-76, the Central Government has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the demand of the workmen employed in Bagalia Sand Stone Mines in the District of Bundi (Rajasthan) of Shri Hiralal Mewara, Mewara Stone Company, Kottari Chouraha, Kota for grant of paid national and festival holidays is justified ? If so, on what occasions and from which year ?"

Notices were issued to the parties concerned in the dispute to put appearance and submit their respective statements of claims. None of the parties appeared before me. On 10th January, 1977, a mutual settlement in writing made by the parties was received in this Tribunal by post. It was stated therein that the parties have arrived at a mutual settlement and an award may be passed in accordance with the terms mentioned therein.

Since, the parties have arrived at a mutual settlement, the following award is passed in terms of it.

The following paid national and festival holidays shall be observed by the employer with effect from January 1, 1976 and onwards.—

S.No.	Name of Holiday.	Day.
1.	26th January—Republic Day.	1
2.	Holika Dahan (Dhulendi).	1
3.	Raksha Bandhan.	1
4.	15th August—Independence Day.	1
5.	Deepawali.	1
6	2nd October, Gandhi Jayanti.	1

The employer shall make payment of wages of the above holidays to his workmen for the year 1976 on or before 31-1-1977.

The award be submitted to the Central Government for publication in accordance with law.

12th Jany. 1977

S. S. BYAS, Presiding Officer

[L-29011/11/76-D III B]

V. VELAYUDHAN, Under Secy.

CORRIGENDUM

S.O. 563.—In the Order of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2647, dated the 10th May, 1976, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th July, 1976, at pages 2538-2539, in para 1, *for* the word "workmen" *read* "workman".

[No. L-20012/160/75/DIIIA]

S. H. S. IYER, Desk Officer.

New Delhi, the 18th January, 1977

S.O. 564.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator in the industrial dispute between the management of Bhilai Steel Plant (Mines), Hindustan Steel Limited, Bhilai and their workmen which was received by the Central Government on the 15th January, 1977.

BEFORE THE DY. CHIEF LABOUR COMMISSIONER (C) AND ARBITRATOR

In the matter of arbitration of an industrial dispute under section 10A of the ID Act, 1947 between the Mines management of Bhilai Steel Plant and their workman Shri S. N. Jha, Ural Drill Operator of Nandini Mines represented by Metal Mines Workers Union (INTUC) about alleged discriminatory fixation of his seniority as Ural Drill Operator.

PARTIES :

(1) Management of Bhilai Steel Plant, Bhilai.

(2) Metal Mine Workers Union Nandini, Distt. Durg.

(3) Shri R. S. Mudar.

For Employer.—(1) Shri R.S. Thakur, Personnel Officer.

For Workman.—(1) Shri G. P. Shukla, Secretary, Metal Mines Workers Union, Nandini.

(2) Shri S. N. Jha.

INDUSTRY : Iron Ore Mines

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by Order No. L-26013(4)/76-D. IV(B) dated 26th July 76 published an arbitration agreement entered into on 2-4-76 by the above parties referring the following specific matter in dispute for my arbitration under section 10A of the I.D. Act 1947.

"Whether the seniority of Shri S. N. Jha, Ural Drill Operator has been fixed in a discriminatory manner. If so, whether as a result of such fixation of seniority, he has been superseded in the matter of promotion ? If so to what relief he is entitled to ?"

The agreement dated 2-4-76 provided for the Award to be given by 26-10-76, but this period was extended by mutual consent upto 26-1-77.

The parties were requested on 21-8-76 to submit their written statements within 10 days of the receipt of the letter. The union submitted their written statement on 1-9-76 and the management on 14-9-76 each with a copy to the other party. The Union submitted a re-joinder on 29-9-76.

On 6-10-76, the first date of hearing the management's representative raised a preliminary objection to the presence of union representatives representing the case on the plea that they did not bring letters of authority. After verifying the position I allowed the representative to present their cases. The management's representative also requested to make Shri R. K. Mudar as a party to the proceedings. Shri R. S. Mudar made an application on 26-7-76 (received on 15-9-76) for being impleaded as party to the dispute and for affording an opportunity to present his case.

At the hearing on 23-11-76 though Shri Mudar was not present but with the consent of the parties he was impleaded as a party and next hearing was fixed for 7th Dec., 1976. Shri Mudar telegraphically requested for copies of statements

and rejoinder submitted by the management and Metal Mines workers Union for filing his written statement. The concerned party were directed to give all the written statements to Shri Mudar and hearing was finally fixed for 27th Dec., 1976 at which the parties mentioned above were present but Shri Mudar did not enter any appearance despite adequate notice and no communication was received from him. In the circumstances I had to proceed in the arbitration without Shri Mudar. The written statement of Shri Mudar was received on 21-12-76 was duly considered in his absence.

The Bhilai Steel Plant management is the employer of the workman Shri S. N. Jha having employed him as Ural Drill Operator in its captive mines at Nandini.

During 1965 a new type of equipment known as Ural Drill was installed at Mines (Rajhara & Nandini) and the management decided to impart in-plant training to suitable candidates after an open selection and provide opportunity for them to be appointed as Ural Drill Operator.

Consequent to this policy decision, trainees were selected by open interview from amongst the candidates who had applied and a selection panel was drawn upon 4-9-65 with marks as indicated below :—

S No.	Name	Place of posting	No. of marks at Selection panel
	S/Shri		
1.	R. S. Mudar	Nandini	25
2.	A. R. Nair	Rajhara	25
3.	Subhash Chandra	Nandni	25
4.	P. N. Singh	Nandini	25
5.	K. Karunakaran	Rajhara	25
6.	C. R. Bakshi	Nandini	26
7.	K. K. Tilakan	Rajhara	25
8.	Rudra Pal Singh	Nandini	25
9.	Tushar Kanti Ray	Rajhara	29
10.	A. K. Dutta	Rajhara	27
11.	S. N. Jha	Nandini	28
12.	S. N. Sarkar	Rajhara	26

Shri S. N. Jha was selected alongwith others and put to training.

On successful completion of the training Shri S. N. Jha was appointed alongwith others as Ural Drill Operator at Nandini Mines on 22-11-65. The result of test on 18-11-65 is as under :—

S. N.	Name	Total Marks	Marks obtained
	S/Shri		
1.	R. S. Mudar	100	68
2.	A. R. Nair	100	79
3.	Subhash Chandra	100	76
4.	P. N. Singh	100	76
5.	K. Karunakaran	100	73
6.	C. R. Bakshi	100	80
7.	K. K. Tilakan	100	82
8.	Rudra Pal Singh	100	86
9.	Tushar Kanti Ray	100	86
10.	A. K. Dutta	100	61
11.	S. N. Jha	100	65
12.	S. N Sarkar	100	65

The management placed Shri S. N. Jha as the junior most amongst the Ural Drill Operators posted at Nandini. He was made junior to S/Shri C. R. Bakshi, R. S. Baghel, P. N. Singh and R. S. Mudhar all of who were appointed alongwith him on the same date. All these persons were subsequently promoted as Chargeman as per seniority and Shri S. N. Jha continued as Ural Drill Operator till date at Nandini Mines.

The Union made the following submission :—

(i) The rules for fixing seniority was/is prescribed at Plant level by orders issued by General Manager of Bhilai Steel Plant and such rules are applicable to the whole plant and its captive mines which include Nandini Mines and Rajhara Mines.

(ii) The principles of seniority was notified vide order No. MPS/64/Sen122 dated 2/5-3-64 and these principles were in force during 1965 and therefore, the seniority of Shri S. N. Jha and other should have been fixed as per the policy contained in the above order.

(iii) All Ural Drill Operators completed their training on the same date on 22-11-65 and their was a tie in fixing their seniority and this would have been resolved on the basis of their placement in the selection panel as trainee as per the procedure in force then.

(iv) The inter-se-seniority of Ural Drill Operators appointed in the regular post on the same date after completion of training alongwith Shri S. N. Jha, and posted to Rajhara Mines was fixed by the management correctly, as per their position in the selection panel as trainees and in accordance with the circular 122 dated 5-3-64.

(v) In view of the position explained above the seniority of Shri S. N. Jha was not fixed in accordance with the principles of seniority then prevailed and also applied to his counter-parts at Rajhara Mines. Therefore the fixation was in a discreminatory manner.

By this discreminatory action on the part of management Shri S. N. Jha was not only deprived of his proper place in seniority position as Ural Drill Operator but also his legitimate chances of promotion to the post of Chargeman, being the senior most.

Management's representative made the following submission :—

(i) On being posted after successful completion of training and examination Shri S. N. Jha was placed in order of seniority as per his performance in the trade test i.e. as per marks obtained by him. He was thus correctly placed at Sl. No. 6. This conforms to the management's policy as per DGM's circular No. IV/8(1)/B/61 dated 11-9-61.

(ii) Since the persons were selected as trainees only and as they were carrying their original designation till completion of training and test, there was no question of reckoning their seniority on the basis of selection as trainee.

(iii) Stretching of imagination to compare with other areas is not justified as the treatment at Nandini Mines to this specific category of Ural Drill Operator is uniform and homogeneous conforming to the laid down policies of maangement.

(iv) Management stated that seniority was in accordance with order dated 11-9-61 and Shri S. N. Jha did not appear in the Trade Test.

I have verified the placement of persons as per the selection pannel of UDO Trainees from the records produced by the management at my request. This shows a combined list of 12 persons of both Rajhara and Nandini Mines and Shri S. N. Jha stands next to Shri T. K. Rai of Rajhara Mines, on the basis of marks obtained 10 other persons of both Rajhara and Nandini mines are placed below Shri S. N. Jha having obtained lesser marks as per this list. Management have not contradicted and the fact remains that seniority at Rajhara was fixed based on the placement of individuals on this selection panel. It is also fact that the seniority at Nandini Mines of persons of the same selection list was fixed in a different manner i.e. as per the marks obtained on the performance of the individuals in a test after training.

The management have produced a circular of DGM, BSP dated 11-9-61 which was applicable to both captive mines that policy of fixation of seniority was uniform both these mines/units, especially so when the circular calling for applications, selection list, offer of appointment, performance test etc. were done jointly. Where as the union has cited circular No. MPS/64/Sen/122 dt. 5-3-64 which was the latest when seniority of UDOs were to be decided in 1965. It is also

clear that seniority of UDOs at Rajhara Mines was fixed on the principle contained in this circular. Seniority list of Ural Drill Operators was made in January, 1969.

Thus management has not followed a uniform policy. I do not find much substance in the contention of the management that comparision with Rajhara Mines is not jusified, in this particular issue.

On enquiry I was told that Trade Test was not properly conducted as representatives of General Manager Bhilai Technical Institute concerned Department Head and Personnel Department and Departmental Head representatives had not signed the Trade Test and therefore there is little value for seniority purposes. In view of all the above I am of the opinion that the seniority of Shri S. N. Jha has not been fixed properly and obviously there has been discrimination in seniority. Shri S. N. Jha should be placed at serial number one in the seniority list of UDOs of Nandini as on 22-11-65. He is entitled for all benefits of this seniority. Monetary benefits if any, may be given within 2 months of the Award becoming enforceable.

I award accordingly in term stated in earlier para.

Given this award under my Seal and Signature the 31st day of December, 1976.

P. C. RAI,
Dy. Chief Labour Commissioner(C) & Arbitrator.

[No. L-26013(4)/76-D-IV(B)]

BHUPENDRA NATH, Desk Officer

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1977

का० आ० 565.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ङ के उप-खंण्ड (vi) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3090, तारीख 7 अगस्त, 1976 द्वारा भारत सरकार टकसाल, अलीपुर, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 7 अगस्त, 1976 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त कालावधि के आगे छः मास की कालावधि के लिए बढ़ाया जाना लोकहित में अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 7 फरवरी, 1977 से आगे छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस० 11020/3/77/डी० I (ए)]

एल० के० नारायणन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th January, 1977

S.O. 565.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3090 dated the 7th August, 1976, the India Government Mint, Alipore, Calcutta, to be public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 7th August 1976 ;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 7th February, 1977.

[No. S. 11020/3/77/DI(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1976

का० आ० 566.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री टी० पालानियाप्पन, बी०ए०, बी०एल०, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के समक्ष लंबित है;

और उक्त श्री टी० पालानियाप्पन बी०ए०, बी०एल०, की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री टी० पालानियाप्पन, बी०ए०, बी०एल०, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, मद्रास से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा-7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, मद्रास को, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी०एन० सिगारवेलु, बी०ए०, बी०एल०, होंगे, इस निदेश के साथ अंतरित करती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मद्रास और आगे कार्रवाई उसी आयाम से करेगा जिस पर वे उसे अंतरित की जायें और विधि के अनुसार उनका निपटारा करेगा।

अनुसूची

क्रमांक	विवाद संख्या	आदेश संख्या	विवाद के पक्षकार
1	2	3	4
1.	आई०डी० संख्या 44/74	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12011/6/74-एल आर-3, तारीख 7-11-74	साउथ इंडियन बैंक लि०, त्रिचुर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
2.	आई० डी० संख्या 46/74	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-35011/7/74-पी डी/सी एम टी, तारीख 17-12-74	मैसर्स कोल्लिल्स लाइन (प्राइवेट) लि०, स्टीमर ओनर्स, कोचीन के कर्मकार और और प्रबन्धतंत्र
3	आई०डी० संख्या 49/74	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-35011/5/74-पी एण्ड डी/सी एम टी, तारीख 26-12-74	मैसर्स कोल्लिस लाईन (प्राइवेट) लि०, कोचीन के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
4.	आईडी० संख्या 28/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12025/12/73-एल आर-3, तारीख 24-3-76	बैंक आफ मदुराई लि०, केन्द्रीय कार्यालय, मदुराई के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
5.	आई०डी० संख्या 14/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12011/14/74-एल आर-3, तारीख 26-2-75	इंयियन बैंक, मद्रास-1 के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र

1	2	3	4
6.	आई०डी० संख्या 19/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12011/2/75-डी 2, ए तारीख 11-3-75	साउथ इंडियन बैंक लि०, त्रिचूर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
7.	आई०डी० संख्या 2975	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-11011/17/74 एल आर-3/डी 2 बी, तारीख 11-4-75	इंडियन एयरलाइन्स मद्रास के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
8.	आई०डी० संख्या 34/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12011/4/75-डी-2ए, तारीख 15-5-75	साउथ इंडियन बैंक लि०, त्रिचूर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
9.	आई डी० संख्या 35/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12011/8/74-एल आर-3, तारीख 17-5-76	मैसर्स साउथ इंडियन बैंक लि०, त्रिचूर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
10.	आई०डी० संख्या 46/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-35012/1/75-डी-4 ए, तारीख 8-7-75	मैसर्स साउथ इंडिया कारपोरेशन एजेन्सीज (प्रा०) लि०, मद्रास-1 के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
11.	आई०डी० संख्या 48/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-29011/33/75-डी-3 बी तारीख 9-7-75	वि केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लि०, क्युलोन के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
12.	आई०डी० संख्या 51/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12011/14/75-डी 2 ए, तारीख 21-7-75	बैंक आफ मदुराई लि० मदुराई, के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
13.	आई०डी० संख्या 52/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12012/68/75-डी-2 ए, तारीख 22-7-75	बैंक आफ मदुराई लि०, मदुराई के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
14.	आई०डी० संख्या 55/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-42012/77/75-डी-2 ए, तारीख 25-7-75	साउथ इंडियन बैंक लि० त्रिचूर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
15.	आई०डी० संख्या 57/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-42011/1/75-डी-2 बी, तारीख 30-7-75	भारतीय खाद्य निगम की माडर्न राइस मिल के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
16.	आई०डी० संख्या 60/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-11011/2/75-डी-2 ए तारीख 13-8-75	इंडियन एयरलाइन्स मद्रास के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
17.	आई०डी० संख्या 61/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12012/50/75-डी-2 ए, तारीख 19-8-76	बैंक आफ बड़ोदा, मद्रास के कर्मकार और प्रबंधतंत्र
18.	आई०डी० संख्या 66/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-29011/95/75-डी-3 बी, तारीख 11-8-75	मैसर्स इंडिया सीमेंट्स लि० शंकर नगर, रिरूनेलवेली, जिले के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
19.	आई०डी० संख्या 70/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-35012/3/75-डी-4 ए, तारीख 20-9-75	मैसर्स हरिसन्स एण्ड क्रासफील्ड लि०, कोचीन के कर्मकार और प्रबंधतंत्र
20.	आई०डी० संख्या 73/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-42012/51/74-एल आर 3/डी 2 बी, तारीख 30-9-75	भारतीय खाद्य निगम (पत्तन प्रक्रियाएं) । मद्रास के कर्मकार और प्रबंधतंत्र
21	आई०डी० संख्या 83/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-29011/125/75-डी 3 बी, तारीख 27-11-75	मैसर्स डालमिया मैगनेसाइट कारपोरेशन सेलम-5 के कर्मकार और प्रबंधतंत्र
22	आई०डी० संख्या 84/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-29011/127/75-डी 3बी, तारीख 29-11-75	मैसर्स डालमिया मैगनेसाइट कारपोरेशन, सेलम-5 के कर्मकार और प्रबंधतंत्र
23.	आई०डी० संख्या 85/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-42012/39/74-एल आर 3, तारीख 4-12-75	भारतीय खाद्य निगम, मद्रास के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
24.	आई०डी० संख्या 87/75	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12011/30/75-डी-2 ए, तारीख 15-12-75	बैंक आफ मदुराई लि०, मदुराई के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
25.	आई०डी० संख्या 1/76	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12011/34/75-डी-2 ए, तारीख 5-1-76	ग्रिंडलेज बैंक लि०, मद्रास के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
26.	आई०डी० संख्या 2/76	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-35012/4/75-डी-4 ए, तारीख 6-1-75	मैसर्स सीताराम बेयरहाउस क्लीरिंग, फारवर्डिंग, एण्ड शिपिंग एजेंट्स, कोचीन-3 के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
27.	आई०डी० संख्या 4/76	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12011/31/75-डी-2ए, तारीख 20-1-76	इंडियन ओवर सीज बैंक, मद्रास-2 के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
28.	आई०डी० संख्या 6/76	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-29011/126/75-डी-3 बी, तारीख 29-1-76	मैसर्स डालमिया सीमेंट्स (भारत) लि०, डालमियापुरम के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र

1	2	3	4
29.	आई०डी० संख्या 7/76	भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय का आदेश संख्या एल-29011/110/75-डी 3 बी, तारीख 29-1-76	मैसर्स डालमिया मैगनसाइट कारपोरेशन, सेलम-5 के कर्मकार और प्रबंधतंत्र
30	आई०डी० संख्या 8/76	भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय का आदेश संख्या एल-29011/137/75-डी-3 बी, तारीख 31-1-76	मैसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लि० डालमिया पुरम, तिरुची जिला के कर्मकार और प्रबंधतंत्र
31.	आई०डी० संख्या 15/76	भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय का आदेश संख्या एल-42011/1/75-डी-2 बी, तारीख 18-2-75	भारतीय खाद्य निगम की माईन राइस मिल, सम्बातारकोयल के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र तथा श्री मुथुस्वामी आय्यर, ठेकेदार
32	आई०डी० संख्या 18/76	भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय का आदेश संख्या एल-29011/132/75-डी-3 बी, तारीख 27-2-76	चेट्टीनाद सीमेंट कारपोरेशन, पुलियूर की अलम्बादी लाइम स्टोन माइन्स के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र
33.	आई०डी० संख्या 21/76	भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय का आदेश संख्या एल-13012/5/75-डी-11 बी, तारीख 22-3-76	कैन्टोनमेंट बोर्ड वेल्लिंगटन, नीलगिरिज जिला के कर्मकार और प्रबंधतंत्र
34	आई०डी० संख्या 47/75	भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय का आदेश संख्या एल-29011/76/74-एल० आर० IV तारीख 17-12-74	मैसर्स स्टार कन्स्ट्रक्शन एण्ड ट्रांसपोर्ट कं०, सकरी वैस्ट, डाकघर सेलम, जिला के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र

[फा० सं० एल-12025/23/76-डी० II ए]

ORDER

New Delhi, the 29th August, 1976

S.O. 566.—Whereas the Industrial [Disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri T. Palaniappan, B.A., B L. Presiding Officer, Industrial Tribunal, Madras;

And whereas the services of the said Shri T. Palaniappan, B.A., B.L. are no longer available;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Govt. hereby withdraws the proceedings in relation to the said disputes from Shri T. Palaniappan, B.A., B.L., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Madras and transfers the same to the Industrial Tribunal, Madras, presided over by Shri T.N. Singharavelu, B. A., B. L., constituted Under Section 7-A of the said Act and directs that the said Central Government Industrial Tribunal, Madras shall proceed with the same proceedings from the State at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Dispute No.	Order No.	Parties to the dispute
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	I.D. No. 44/74	L-12011/6/74-LR. III dt. 7-11-74 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of South Indian Bank Ltd. Trichur.
2.	I.D. No. 46/74	L-35011/7/74-PD/CMT. dt. 17-12-74 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of M/s. Collis Line (Private) Ltd. Steamer Owners, Cochin.
3.	I.D. No. 49/74	L-35011/5/74/P&D/CMT. dt. 26-12-74 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of M/s. Collis Line (Private) Ltd. Cochin.
4.	I.D. No. 28/75	L-12025/32/73-LR. III. dt. 24-3-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Bank of Madras Ltd. Central Office Madurai.
5.	I.D. No. 14/75	L-12011/14/74-LR. III dt. 26-2-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Indian Bank Madras-1.
6.	I.D. No. 19/75	L-12011/2/75/D-II.A dt. 11-3-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of South Indian Bank Ltd. Trichur.
7.	I.D. No. 29/75	L-11011/17/74-LR. III/D-II.B dt. 11-4-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Indian Airlines, Madras.
8.	I.D. No. 34/75	L-12011/4/75-D.II.A dt. 15-5-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of South Indian Bank Ltd. Trichur.
9.	I.D. No. 35/75	L-12011/8/74-LR.III dt. 17-5-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of South Indian Bank Ltd., Trichur.
10.	I.D. No. 46/75	L-35012/1/75-D-IV A. dt. 8-7-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of M/s. South India Corporation Agencies (Pvt.) Ltd., Madras-1.
11.	I.D. No. 48/75	L-29011/33/75/D III B dt. 9-7-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of the Kerala Minerals and Metals Ltd. Quilon.

1	2	3	4
12.	I.D. No. 51/75	L-12011/14/75-D-IIA dt. 21-7-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Bank of Madurai Ltd., Madurai.
13.	I.D. No. 52/75	L-12012/68/75-D-IIA dt. 22-7-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Bank of Madurai Ltd., Madurai.
14.	I.D. No. 55/75	L-12012/77/75-D-IIA dt. 25-7-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of South Indian Bank Ltd., Trichur.
15.	I.D. No. 57/75	L-42011(1)/75-D-IIB dt. 30-7-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Modern Rice Mill of the Food Corporation of India, Sembanar Koil and Shri Muthuswamy Iyer, Contractor.
16.	I.D. No. 60/75	L-11011/2/76/D-IIA dt. 13-8-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Indian Airlines Madras.
17.	I.D. No. 61/75	L-12012/50/75-D-IIA dt. 19-8-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Bank of Baroda, Madras.
18.	I.D. No. 66/75	L-29011/95/75-D-III B dt. 11-8-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of M/s. India Cements Ltd. Sankarnagar, Tirunelveli, District.
19.	I.D. No. 70/75	L-35012/3/75-D-IVA dt. 20-9-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of M/s. Harrisons and Crossfield Ltd. Cochin.
20.	I.D. No. 73/75	L-42012/51/74-LR-III D-II B dt. 30-9-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Food Corporation of India (Port Operations) Madras.
21.	I.D. No. 83/75	L-29011/125/75/D-III B. dt. 27-11-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of M/s. Dalmia Magnesite Corporation, Salem-5.
22.	I.D. No. 84/75	L-29011/127/75-D-III B dt. 29-11-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of M/s. Dalmia Magnesite Corporation Salem-5.
23.	I.D. No. 85/75	L-42012/39/74/LR-III D-II. B dt. 4-12-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Food Corporation of India, Madras.
24.	I.D. No. 87/75	L-12011/30/75/D-IIA dt. 15-12-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Bank of Madurai Ltd., Madurai.
25.	I.D. No. 1/76	L-12011/34/75/D-IIA dt. 5-1-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Grindlays Bank Ltd., Madras.
26.	I.D. No. 2/76	L-35012/4/75/D-IVA dt. 6-1-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of M/s. Sitaram Warehouse Clearing, Forwarding and Shipping Agents, Cochin-3.
27.	I.D. No. 4/76	L-12011/31/75/D-II A dt. 20-1-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Indian Overseas Bank, Madras-2.
28.	I.D. No. 6/75	L-29011/126/75/D-III B dt. 29-1-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of M/s. Dalmia Cements (Bharat) Ltd., Dalmiapuram.
29.	I.D. No. 7/76	L-29011/110/75/D-III B dt. 29-1-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of M/s. Dalmia Magnesite Corporation, Salem-5.
30.	I.D. No. 8/76	L-29011/137/75/D-III B dt. 31-1-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of M/s. Dalmia Cement (Bharat) Ltd. Dalmiapuram, Tiruchi Dist.
31.	I.D. No. 15/76	L-42011/1/75-D-IIB dt. 18-2-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Modern Rice Mill of the Food Corporation of India, Semba Narkoil and Sri Muthuswamy Iyer, Contractor.
32.	I.D. No.18/76	L-29011/132/75-D-III B dt. 27-2-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Alambadi Lime Stone Mines of Chettinad Cement Corporation, Puliyur.
33.	I.D.No.21/76	L-13012/5/75/D-IIB dt. 22-3-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Cantonment Board Wellington, Nilgiris Dist.

1	2	3	4
34	I D No 47/74	L-29011/76/74-LR-IV dt 17-12-74 of the Ministry of Labour, Govt of India	Workmen and the management of M/s Star Construction & Transport Co, Sankari West, P O Salem Dist

[F No L-12025/23/76-D IIA]

आदेश

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1976

का० आ० 567 —इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री टी० नरसिंह राव, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद, के समक्ष लम्बित है ,

और श्री टी० नरसिंह राव की सेवाएं अब उपलब्ध नही रही है ,

अत, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33ख की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री टी० नरसिंह राव पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियो को वापस लेती है और उन्हे उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद को, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के० पी० नारायण राव, बी०ए० बी०एल० होगे, इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद और आगे कार्यवाई उसी प्रक्रम से करेगा जिस पर वे उसे अंतरित की जाए और विधि के अनुसार उनका निपटारा करेगा ।

अनुसूची

क्रमांक	औद्योगिक विवाद सख्या	आदेश सख्या	विवाद के पक्षकार
1	2	3	4
1	72/71	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-2112/29/71-एल-आर 11, तारीख 19-10 71	
2	87/71	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-2112/32/71-एल० आर-11, तारीख 3-12-1971	
3	1/72	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-2112/27/1971-एल आर०-11, तारीख 29-12-1971	
4	3/73	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-34011/8/72/पी०एड डी०, तारीख 19-1-73	कांटिनेन्टल कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट) लि०, विशाखापतनम के कर्मकार और प्रबन्धतत्र ।
5	27/74	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-34012/3/74-पी०डी० सी०एम०टी०, तारीख 25-9-74	कांटिनेन्टल कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट) लि० विशाखापतनम के कर्मकार और प्रबन्धक ।
6	35/74	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-34012/4/74 पी०डी०/सी०एम०टी०, तारीख 21-10-74	कांटिनेन्टल कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट) लि०, विशाखापतनम के कर्मकार और प्रबन्धतत्र ।
7	37/75	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-34011/14/74 पी डी/सी एम टी तारीख 19-10-74	कांटिनेन्टल कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट) लि०, विशाखापतनम के कर्मकार और प्रबन्धतत्र ।
8	10/75	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-42012/6/65-डी 11 बी, तारीख 17/18 3-75	तुगभद्रा बोर्ड, बेल्लारी कैन्टोनमेंट के कर्मकार और प्रबन्धतत्र ।
9	31/75	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-26011/10/75-डी-4 बी, तारीख 21-7-75	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० बेल्लारी जिले के कर्मकार और प्रबन्धतत्र ।
10	41/75	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-21011/13/75-डी 3 बी, तारीख 22 9-75	सिगरेनी कोलियरीज क० लि०, अदीलाबाद, जिला, आन्ध्र प्रदेश के कर्मकार और प्रबन्धतत्र ।
11.	2/76	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-34012/5/75-डी-1-ए, तारीख 27 1 76	मैसर्स कांटिनेन्टल कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट) लि०, विशाखापतनम के कर्मकार और प्रबन्धतत्र ।
12	3/76	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-21011/8/75 डी 3 बी, तारीख 12-2-76	सिगरेनी कोलियरीज क० लि०, करीमनगर जिला आन्ध्र प्रदेश के कर्मकार और प्रबन्धतत्र ।
13	5/76	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-12012/169/75-डी-2 ए, तारीख 19-2-76	स्टेट बैंक आफ इडिया, हैदराबाद के कर्मकार और प्रबन्धतत्र ।
14	6/76	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-12012/166/75 डी-2-ए, तारीख 11-3-76	स्टेट बैंक आफ इडिया, हैदराबाद के कर्मकार और प्रबन्धतत्र ।
15	7/76	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-12012/168/75-डी-2 ए तारीख 11-3-76	स्टेट बैंक आफ इडिया, हैदराबाद के कर्मकार और प्रबन्धतत्र ।
16	8/76	भारत सरकार, श्रम मत्रालय का आदेश सख्या एल-12012/188/75-डी-2 ए तारीख 11-3-76	स्टेट बैंक आफ इडिया, हैदराबाद के कर्मकार और प्रबन्धतत्र ।

1	2	3	4
17.	9/76	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12012/190/75-डी-2, ए तारीख 11-3-76	स्टेट बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
18	10/76	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12012/191/75 डी 2, ए तारीख 11-3-76	स्टेट बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
19.	11/76	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12012/192/75-डी 2-ए, तारीख 11-3-76	स्टेट बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
20.	12/76	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश,संख्या एल-12012/193/75-डी-2, तारीख 11-3-76	स्टेट बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
21.	13/76	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12012/194-75 डी 2, ए तारीख 11-3-76	स्टेट बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
22.	14/76	भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का आदेश संख्या एल-12012/165/75-डी 2, ए तारीख 19-3-76	स्टेट बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।

[फा० सं० एल 12025/52/76-डी, 2 ए]

ORDER

New Delhi, the 5th October, 1976

S.O. 567.—Whereas the Industrial Disputes specified in in the Schedule hereto annexed are pending before Shri T. Narasing Rao, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad.

And whereas the services of the said Shri T. Narasing Rao, are no longer available.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said disputes from Shri T. Narasing Rao, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad and transfers the same to the Industrial Tribunal, Hyderabad, presided over by Shri K.P. Narayana Rao, B.A., B.L. constituted under Section 7-A of the said Act and directs that the said Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad shall proceed with the same proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Industrial Disputes No.	Order No.	Parties to the dispute
1	2	3	4
1	72/71	L-2112/29/71-LR.II dt. 19-10-71 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	
2.	87/71	L-2112/32/71-LR.II dt. 3-12-1971 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	
3.	1/72	L-2112/27/71/LR. II dt. 29-12-1972 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	
4.	3/73	L-34011/8/72-/P&D dt. 19-1-73 of Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Continental Construction (Private Ltd., Visakhapatnam.
5.	27/74	L-34012/3/74-PD/CMT dt. 25-9-74 of Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Continental Construction (Private) Ltd., Visakhapatnam.
6.	35/74	L-34012/4/74/PD/CMT. dt. 21-10-74 of Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Continental Construction (Private) Ltd., Visakhapatnam.
7.	37/75	L-34011/14/74/PD/-CMT. dt. 19-10-74 of Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Continental Construction (Private) Ltd., Visakhapatnam.
8.	10/75	L-42012/6/75/DIIB dt. 17/18-3-75 of Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Tungabhadra Board, Bellary Cantonment.
9.	31/75	L-26011/10/75-/DIV (B) dt. 21-7-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of National Mineral Development Corpn. Ltd. Bellary District.
10.	41/75	L-21011/13/75/D.3B dt. 22-9-75 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Singareni Collieries Co. Ltd Adilabad Dist. A.P.
11.	2/76	L-34012/5/75DIV A. dt. 27-1-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of M/s. Continental Construction (Pvt.) Ltd. Visakhapatnam.
12.	3/76	L-21011/8/75/D.3B dt. 12-2-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of Singareni Collieries Co. Ltd., Karimnagar Dist. A.P.

1	2	3	4
13.	5/76	L-12012/169/75/D.II. A. dt. 19-2-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of State Bank of India, Hyderabad.
14.	6/76	L-12012/166/75/D.II A. dt. 11-3-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of State Bank of India, Hyderabad.
15.	7/76	L-12012/168/75-D.II A. dt. 11-3-1976 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of State Bank of India, Hyderabad.
16.	8/76	L-12012/188/75/D-II. A. dt. 11-3-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of State Bank of India, Hyderabad.
17.	9/76	L-12012/190/75-D.II. A. dt. 11-3-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of State Bank of India, Hyderabad.
18.	10/76	L-12012/191/75-D.II A. dt. 11-3-76 of th Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of State Bank of India, Hyderabad.
19.	11/76	L-12012/75/D-II A. dt. 11-3-76 of the Ministry of Labour Govt. of India.	Workmen and the management of State Bank of India, Hyderabad.
20.	12/76	L-12012/193/75/D.II A. dt. 11-3-76 of the Ministry of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of State Bank of India, Hyderabad.
21.	13/76	L-12012/1-94/75/D-II.A dt. 11-3-76 of the Ministry of Labou Govt. of India.	Workmen and the management of State Bank of India, Hyderabad.
22.	14/76	L-11012/165/75/D. II.A dt. 19-3-76 of the Ministr of Labour, Govt. of India.	Workmen and the management of State Bank of India, Hyderabad.

[F. No. L-12025/52/76/D.II.A]

137 GI/76—7

आदेश

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1976

का०आ० 568.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री यू० एन० माथुर, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, राजस्थान, जयपुर के समक्ष लम्बित है ,

और श्री यू० एन० माथुर की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही है ;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33—ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री यू० एन० माथुर, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, राजस्थान, जयपुर से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 7—क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, राजस्थान, जयपुर को, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस० एस० व्यास, बी० ए०, एल० एल० बी० होंगे, इस निदेश के साथ अंतरित करती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, राजस्थान, जयपुर और आगे कार्यवाही उसी आयाम से करेगा जिस पर उसे अंतरित की जाएं और विधि के अनुसार उनका निपटारा करेगा।

अनुसूची

क्रमांक	विवाद संख्या	आदेश/अधिसूचना संख्या और तारीख	विवाद के पक्षकार
1	2	3	4
1.	सी०आई० टी०-4/72	एल०25011(1)/72-एल० आर०-4 तारीख 30-9-72	जयपुर उद्योग लि० सवाई-माधोपुर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।
2.	सी०आई० टी०30/72	10/47/70-एल०आर०-4 तारीख 31-8-71	टंगस्टन खान प्रायोजना, दीगाना के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।
3.	सी०आई० टी० 37/72	1/14/69/एल०आर०-2 तारीख 2-2-71	पालाना कोलियरी पालाना के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।
4.	सी० आई० टी० 6/73	एल-2901138/71-एल० आर०-4 तारीख 11-1-73	जयपुर उद्योग लि० सवाई-माधोपुर के कर्मकार और प्रबंध तंत्र।
5.	सी० आई० टी० 12/73	एल० 29011/6/73-एल० आर०-4 तारीख 19-2-72	जयपुर उद्योग लि० सवाई-माधोपुर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।
6.	सी० आई० टी० 13/73	एल० 12012/161/72-एल० आर०-3 तारीख 1-3-73	पंजाब नेशनल बैंक, जयपुर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।
7.	सी० आई० टी० 16/73	एल० 12012/3/73-एल० आर०-3 तारीख 12-9-73	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।
8.	सी० आई० टी०-3/73	एल० 12012/3/74-एल० आर०-3 दिनांक 6-6-74	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जयपुर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र।

1	2	3	4
9	सी० आई० टी० 4/74	एल० 12012/79/73-एल० आर०-3 तारीख 19-8-74	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जयपुर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
10	सी० आई० टी० 1/75	एल०-12012/82/74-एल० आर०-3 तारीख 22-1-75	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जयपुर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
11	सी० आई० टी० 3/75	एल० 41012/7/74-एल०-आर०-3 डी-2बी तारीख 16-4-75	उत्तर रेलवे, बीकानेर के कर्मकार और प्रबंधतंत्र ।
12.	सी० आई० टी० 6/75	एल-12012/49/75-डी-3 ए तारीख 5-7-75	यूनाइटेट कमर्शियल बैंक, जयपुर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
13	सी० आई० टी० 7/75	एल० 12012/56/72-एल० आर०-3 तारीख 24-5-75	पंजाब नेशनल बैंक इंदौर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
14	सी० आई० टी० 8/75	एल०-12012/27/73-एल आर०-3 तारीख 23-7-75	पंजाब नेशनल बैंक के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
15.	सी० आई० टी० 9/75	एल-42012/36/74-एल-आर०-3 डी० 2बी तारीख 26-7-75	राजस्थान पावर एटोमिक इनर्जी, कोटा के कर्मकार और प्रबन्धतन्त्र ।
16.	सी० आई० टी० 10/75	एल-41011/17/73/एल०-आर०-3 डी 2 बी तारीख 18-8-75	वैस्टर्न रेलवे, बम्बई के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
17.	सी० आई० टी० 11/75	एल-42012/41/75-डी० 2 ए० तारीख 19-9-75	पजाब नेशनल बैंक, जयपुर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
18.	सी० आई० टी० 12/75	143/11/3/75-डी 4 बी० तारीख 4-10-75	खेत्री कोपर प्रोजेक्ट, खेत्री, के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
19.	सी० आई० टी० 13/75	एल० 12012/48/75-डी-2 ए० तारीख 10-11-75	बैंक आफ बड़ौदा के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
20.	सी० आई० टी० 14/75	एल-12012/138/75-डी० 2 ए तारीख 13-11-75	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, जयपुर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
21	सी० आई० टी० 15/75	एल-12012/130/75-डी० 2 ए तारीख 25-11-75	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, जयपुर के कर्मकार और और प्रबन्धतंत्र ।
22.	सी० आई० टी० 1/76	एल०-12012/142/75-डी-2 ए० तारीख 12-1-76	स्टेट बैंक आफ इंडिया, जयपुर के कर्मकार और प्रबंध तंत्र ।
23.	सी० आई० टी० 2/76	एल०-12012/141/75-डी-2ए० तारीख	स्टेट बैंक आफ इंडिया जयपुर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
24	सी० आई० डी० 3/76	एल-12012/145/73-एल० आर०-3 तारीख 28/1/76	पजाब नेशनल बैंक, जयपुर के प्रबन्धतंत्र और कर्मकार ।
25.	सी० आई० टी० 8/76	एल-12012/160/75-डी 2 ए तारीख 25-3-76	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, जयपुर के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
26.	सी० आई० टी० 9/76	एल-42012/38/74-एल० आर०-3 डी० 3 बी० तारीख 19-5-76	हैवी वाटर प्रोजेक्ट, डाकघर अनुशक्ति कोटा के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।
27	सी० आई० टी० 10/76	एल-19011/11/76-डी-3 बी० तारीख 7-6-76	मेवाड़ा स्टोन कम्पनी, कोठारी चौराहा कोटा के कर्मकार और प्रबन्धतंत्र ।

[सं० 12025/86/76/डी-2 ए०]

ORDER

New Delhi, the 27th November, 1976

S O 568.—Whereas the Industrial Disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri U.N. Mathur, Presiding Officer, Central Govt. Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur;

And whereas the services of the said Shri U N. Mathur are no longer available ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Govt. hereby withdraws the proceedings in relation to the said disputes from Shri U N. Mathur, Presiding Officer, Central Govt Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur and transfers the same to the Central Govt. Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur, presided over by Shri S.S Byas, B A.L.L.B. constituted under section 7-A of the said Act and directs that the said Central Govt. Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur, shall proceed with the same proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law

SCHEDULE

Sl No.	Dispute No.	Order/INotification No. and Date	Parties to the dispute
1	2	3	4
1.	CIT-4/72	L-25011(1)/72-LR.IV Dt. 30-9-72	Workmen and the management of Jaipur Udhyog Ltd., Sawaimadhopur.
2	CIT-30/72	10/47/70-LR. IV Dt. 31-8-71	Workmen and the management of Tungustan Khar Priyogna, Deegana.
3.	CIT-37/72	1/14/69/LR-II Dt. 2-2-71	Workmen and the management of Palana Colliery, Palana.

1	2	3	4
4.	CIT-6/73	L-29011/38/71-LR. IV Dt. 11-1-73	Workmen and the management of Jaipur Udhyog Ltd., Sawaimadhopur.
5.	CIT-12/73	L-29011/6/73-LR. IV Dt. 19-2-73	Workmen and the management of Jaipur Udhyog Ltd., Sawaimadhopur.
6.	CIT-13/73	L-12012/161/72-LRIII Dt. 1-3-73	Workmen and the management of Punjab National Bank, Jaipur.
7.	CIT-16/73	L-12012/3/73-LR. III Dt. 12-9-73	Workmen and the management of State Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur.
8.	CIT-3/74	L-12012/3/74/LR.III Dt. 6-6-74	Workmen and the management of United Commercial Bank Jaipur.
9.	CIT-4-/74	L-12012/79/73/LR. III Dt. 19-8-74	Workmen and the management of State Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur.
10.	CIT-1/75	L-12012/82/74/LR. III Dt. 22-1-75	Workmen and the management of State Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur.
11.	CIT-3/75	L-41012/7/74/LR III. D-2B. Dt. 16-4-75	Workmen and the management of Northern Railway, Bikaner.
12.	CIT-6-75	I-12012/49/75/D. III. A. Dt. 5-7-75	Workmen and the management of United Commercial Bank, Jaipur.
13.	CIT-7/75	L-12012/56/72/LR. III Dt. 24-5-75	Workmen and the management of the Punjab National Bank, Indore.
14.	CIT-8/75	L-12012/27/73/LR. III Dt. 23-7-75	Workmen and the management of Punjab National Bank.
15.	CIT-9/75	L-42012/36/74/LR. III Dt. D.II.B. Dt. 26-7-75	Workmen and the management of Rajasthan Power Atomic Energy, Kota.
16.	CIT-10/75	L-41011/17/73/LR III. D. II. B. Dt. 18-8-75	Workmen and the management of Western Railway, Bombay
17.	CIT-11/75	L-42012/41/75/D.II.A Dt. 19-9-75	Workmen and the management of Punjab National Bank, Jaipur.
18.	CIT-12/75	143/11/3/75/D-IV-B Dt. 4-10-75	Workmen and the management of Khetri Copper Project, Khetri.
19.	CIT-13/75	L-12012/48/75/D-II. A. Dt. 10-11-75	Workmen and the management of Bank of Baroda, Jaipur
20.	CIT-14/75	L-12012/128/75/D-II. A. Dt. 13-11-75	Workmen and the management of Central Bank of India, Jaipur.
21.	CIT-15/75	L-12012/130/75/D-II. A. Dt. 25-11-75	Workmen and the management of Central Bank of India, Jaipur.
22.	CIT-1/76	L-12012/142/75-D-II. A. Dt. 12-1-76	Workmen and the management of State Bank of India, Jaipur.
23.	CIT-2/76	L-12012/141/75-D. II. A. Dt.	Workmen and the management of State Bank of India, Jaipur.
24.	CIT-3/76	L-12012/145/73-LR. III. Dt. 28-1-76	Workmen and the management of Punjab National Bank, Jaipur.
25.	CIT-8-76	L-12012/160/75-D. II.A. Dt. 25-3-76	Workmen and the management of Central Bank of India, Jaipur.
26.	CIT-9/76	L-12012/38/74-LR. III D. III. B. Dt. 19-5-76	Workmen and the management of Heavy Water Project, P.O. Anushakti, Kota.
27.	CIT-10/76	L-19011/11/76-D-III. B. Dt. 7-6-76	Workmen and the management of Mewara Stone, Company, Kothari Chouraha, Kota.

[F. No. 12025/86/76/D-II.A.]

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1976

का० आ० 569—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कैथोलिक सिरीयन बैंक लिमिटेड, त्रिचूर के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० एन० सिंगारवेलु होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या कैथोलिक सिरीयन बैंक लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र की बैंक की कुन्नमकुलम शाखा के मुख्य लिपिक श्री थाम्बी वरगीस को दिए जाने वाले 49 रुपये प्रति मास के विशेष भत्ते को उनके आदेश संख्या एस/2/244/76 दिनांक 27-7-76 द्वारा 1-8-76 से बन्द करने का प्रस्ताव करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो यह कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[फा० संख्या एल० 12012/165/76-डी 2ए]

आर० पी० नरूला, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th December, 1976

S.O. 569.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Catholic Syrian Bank Limited, Trichur and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sec. 7A and by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal the Presiding Officer of which shall be Shri T. N. Singaravelu with headquarters at Madras refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Catholic Syrian Bank Limited in proposing to withdraw w.e.f. 1-8-76, the Special Allowance of Rs. 49 per month paid to Shri Thambi Verghese, Head Clerk in Kunnamkulam branch of the Bank by their order No. S/2/4244/76 dated 27-7-76 is justified? if not, to what relief is the employees entitled ?

[F. No. L-12012/165/76-D. II. A.]

New Delhi, the 31st January, 1977

S.O. 570.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the State Bank of India Region III, New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on 28-1-77.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

CGID. No. 68 of 1975

BETWEEN

The management of M/s. State Bank of India, New Delhi.

AND

Its workman Shri R. C. Jain, Cashier, Delhi Circle State Bank Staff Association, 33 Bank Enclave Ring Road, Rajouri Garden, New Delhi.

PRESENT :

Shri A. Sheshan—for the management.

Shri J. N. Kapoor—for the workman.

AWARD

The Central Government on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L. 12012/116/75/DII/A. dated the 25th October, 1975 with the following terms of reference :—

"Whether the management of the State Bank of India (Region III) Parliament Street, New Delhi is justified in not transferring Shri R. C. Jain from the clerical cadre to the cash Department ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

2. The applicant averred that he had been working as Cashier at Saharanpur Branch for the last 10 years. He was, then, transferred to Clerical Department by the Bank on six months probation with effect from 15-7-74. It was pleaded that the respondent deferred his claim for officiating chances to higher clerical posts for two years, although he had been officiating as Dy. Head Cashier and Asstt. Head Cashier while in the cash department. He, therefore, made several representations that he be reverted to the cash department but the management did not pay any heed to it. It was pleaded that the action of the respondent in not transferring Shri R. C. Jain from the Clerical Cadre to Cash Department was arbitrary, malafide and act of unfair labour practice and victimisation. It was, therefore, prayed that he be transferred to cash department with effect from the 29-10-74 and be paid wages for all officiating chances and other benefits with effect from 29-10-74.

3. The respondent stated that the transfer from the cash department to the clerical department was made at the request of the workman with effect from 15-7-74. It was admitted that he was not transferred back to the cash department as his conduct in the cash department had not been satisfactory and it was considered that it would not be safe for the Bank to put him back in the cash department. It was pleased that the claim was completely misconceived and untenable in law. It was, herefore, prayed that the claim be rejected.

4. On these pleadings the following issue was framed:—

ISSUE:

1. As in the term of reference.

5. In oral evidence the management examined S/shri M. L. Agarwal—MW1 and D. C. Agarwal—MW2. In rebuttal the workman examined S/shri S. L. Batla-WW1, and Shri R. C. Jain the workman examined himself as WW2.

6. Arguments were, then, heard.

ISSUE NO. : 1

7. In order to appreciate the case of the parties, the following facts may be re-capitulated. The workman, herein, joined the respondent service as a Cashier in 1969. In July, 1974, he was transferred to clerical department at his own request. He, however, felt some difficulty in the clerical department and requested for a re-transfer to the cash department. By his letter dated the 10th September, 1974 (Ex. W/7) the manager of the Saharanpur Branch recommended to the Regional Manager, New Delhi that the workman be transferred to the cash department as also, in view of the acute shortage of cashiers at that branch, he be allowed to continue in the cash department there. This recommendation met with the approval of the Regional Manager, New Delhi who acceded to the request of the workman and allowed him to work in the cash department as cashier. It was communicated to the Branch Manager, Saharanpur by letter dated the 29th October, 1974 (Ex. W/8), The Branch Manager, Saharanpur did not implement the approved transfer. On the 14th February, 1975 he wrote back to the Regional Manager (Ex. M/8), New Delhi that he had not allowed the workman to resume work in the cash department as some important aspect of

the proposal was being examined by him The Branch Manager, again wrote on the 9th May, 1975 (Ex M/7) that the workman was not allowed to revert and resume duties in the cash department because he (the Branch Manager) had been advised by both the accountants (the person-first accountant was previously cash accountant) that the workmans' conduct in cash department was not up to the mark specially with regard to work on exchange counter and issue of new notes The Branch Manager then sought guidance of the Regional Manager by asking in para (2) of Ex M/7 that in view of this background it was for consideration whether the employee with such background be allowed to work in cash department Instructions in the matter from the head office were, then, awaited.

8 Thus, it is evident that the workman, herein, was not transferred from the clerical cadre to the cash department even though this transfer had been approved and ordered by the Regional Office, New Delhi.

9. Now, the case of the management is that the workman was not transferred to the cash department because his conduct in the cash department was not up to the mark specially with regard to work on exchange counter and issue of new notes which had been regretted by the workman himself by his letter Ex M/5

10. The case of the workman is that had he been transferred to the cash department, one Shri W. S. Gill who was already working in the cash department and who was junior to the workman, herein, would not have been given a chance to work on the post of Deputy Head Cashier, meaning thereby that in order to save the promotion of Shri W S. Gill, the workman was not transferred to the cash department, as the former belonged to the recognised union while the letter belonged to a un-recognised union

11 The question that arises for determination thus is whether the conduct of the workman herein, during the period he worked in the cash department from 1964 to July, 1974 was such as could be called not up the mark entailing refusal to be sent back there again

12 Now, so far as the question is concerned, whether his conduct complained about existed or not there is no dispute as the workman admitted that he had exchanged mutilated notes and even full cut notes from a few friends and relatives of his He, also, expressed regret for this conduct and assured the authorities that no such thing would happen in future (See Ex M/5) He, however, had an explanation for it He firstly said that he accepted mutilated notes and even full cut notes to expedite the matter He then, said in his statement WW2 that on account of the alleged misconduct no memos were ever given to him on the ground of defective remittances to the Reserve Bank of India He further said that only recoveries were made in such instances by letters as such defective remittances were found in all banks and about oll cashiers What he meant to say was that the alleged mis-conduct was of no importance and of no penal consequences This evidence given by the workman was corroborated by Shri S L Batla-WW1 He further said that one Shri W. S. Gill who was junior to the workman worked in the cash department and if Shri R C Jain, workman concerned, had been went to the cash department, he would have become the Deputy Head Cashier as he was senior to Shri Gill, who was the Chairamn of the recognised association He further said that sending of cut notes in packets to the Reserve Bank of India and recovery thereof from the clerk cashier was not a lapse but a routine affair No memos were ever given to such cashiers

13 The management failed to give evidence to the effect that sending of cut notes to the Reserve Bank of India was such a mis conduct as entailed penal consequences or such as disqualified a person to be kept in the cash department Shri D C Agarwal-MW2, no doubt, tried to say in his statement MW2 that he considered the lapse on the part of the workman to be such as for which the workman was not fit to be sent to the cash department He, also said that the bank was but to a loss by sending full cut notes to the Reserve Bank of India The management, however, failed to show the loss was actually caused There was no evidence on record that while the full cut notes might have been rejected by the Reserve Bank of India, it actually resulted in a loss to the bank Similarly, Shri D C Agarwal has failed to prove before the Court as to what led him to believe that sending of cut notes to the Reserve Bank of India disqualified a man or made him unfit to a post in the cash department He clearly admitted that there were rules regarding rejection of full cut notes by the Reserve Bank of India He, then, said that disciplinary action could be taken if mutilated notes were accepted by a worker. The rules in that behalf, however, were not put on record, and it remained in the dark as to whether accepting of mutilated and full cut notes was such a lapse as made the workman unfit for being posted to the cash department Moreover, no disciplinary action was taken against the workman at all It, therefore, meant that the lapse in accepting mutilated and full cut notes and sending them to the Reserve Bank of India was not a mis-conduct nor such a mis-conduct as entailed penal consequences. It is, therefore, to be deducted that the alleged lapse on he part of the workmans' evidence that one Shri W S Gill would have only a excuse and was raised as bogey to do down the workman And the reason was not far to seak It was in the workman's evidence that one Shri W S Gill would have suffered loss of promotion if the workman, herein, had been transferred to the cash department and the said Shri W S Gill who was the Chairman of the recognised association had to be saved. The management has not said a word by way of denial that the transfer of Shri R C Jain had nothing to do with the promotion of or saving Shri W. S Gill from loss

14. It is, also, manifest that the Branch Manager, Saharanpur did not implement the transfer of the workman for as many as full 8 months after formal approval had been given to it by the Regional Manager It is, also, un-disputed that Shri D C Agarwal MW2 was the person who recommended the said transfer He, even, wrote to the Regional Manager that the workman be allowed to continue in the cash department at his branch What did then happen which prevailed with him to stop the implementation of the transfer for 8 months. I have no hesitation to infer from the circumstances of this case that it was nothing but the interest of Shri W S Gill which would have suffered if the workman had been transferred to the cash department. Shri D C Agarwal was only looking for some excuse or the other to justify his non-implementation of the approved transfer He could only think of the acceptance of the mutilated and full-cut notes which according to the banks' action, itself, was of no consequences since no action had been taken I am, therefore, of the view that there was no justification for not transferring Shri R C Jain from the clerical cadre to the cash department It was the interest of Shri W S Gill which was being saved by the Branch Manager, Saharanpur which by itself was no justification

15 The issue is, accordingly, decided against the management

16 The workman is, therefore, entitled to the relief of his transfer from the clerical cadre to cash department The management is, directed to transfer Shri R C Jain to the cash department and treat him so, with effect from the first of November 1974 to implement the approval given by the Regional Manager, (Ex W/8) The workman, herein, will then be entitled to all such benefits as may have accrued to him in a manner as if he had been in the cash department on the first of November, 1974. An

Award is made accordingly

(Eight pages)

16th November, 1976

D D GUPTA, Presiding Officer

[F N 12012/116/75-DHA]

S.O 571.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the South Indian Bank Limited, Trichur (Kerala) and their workmen which was received by the Central Government on the 28-1-77

BEFORE THIRU T. N. SINGARAVELU, B.A., B.L.

PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Industrial Dispute No. 35 of 1975.

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of South Indian Bank Limited, Head Office, Trichur (Kerala).

BETWEEN

The workmen represented by.—The General Secretary, South Indian Bank Employees Association, P.B. No. 131, Trichur-1, (Kerala).

AND

The Chairman, South Indian Bank Limited, Head Office, Trichur (Kerala).

Reference :

Order No. L. 12011/8/74-LRIII, dated 17-5-1975 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for final hearing on Monday, the 17th day of January, 1977 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru M. Venugopalan Advocate for the Management and the Union being set exparte and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

This is an Industrial Dispute between the Management of South Indian Bank Limited, Head Office, Trichur (Kerala) and their employees in respect of the matters specified in the reference. This reference was made by the Government of India by its Order No. L. 12011/8/74-LRIII, dated 17-5-1975 of the Ministry of Labour. The issues as framed in the reference are as follows :

(a) Is the management of South Indian Bank Limited, Trichur, justified in not evolving a suitable recruitment policy for Subordinate Staff, clerical staff and for the Officers cadre after discussion with the recognised union of workmen namely the South Indian Bank Employees' Association ? If not, what should be the policy of recruitment that should be adopted by the management of South Indian Bank Limited for the above categories of workmen/officers.

(b) Whether the management of South Indian Bank Limited, Trichur, are justified in appointing clerical staff on a monthly stipend of Rs. 175/- or on a daily rate of Rs. 6/- and peons on a monthly stipend of Rs. 100/- or on a daily rate of Rs. 3-/- per day. If not to what relief and from what date the concerned workmen are entitled ?

(c) Considering item (B) of memorandum of agreement arrived at between the management of South Indian Bank Limited and the All Kerala Bank Employees Federation and South Indian Bank Employees Association on 20th August, 1973 in the presence of the Chief Minister of Kerala, whether the management of South Indian Bank Limited. Trichur justified in refusing to negotiate with the South Indian Bank Employees Association and to frame conditions and methods of promotion of subordinate staff to clerical cadre and of clerical cadre to officers cadre. If not what should be the conditions and methods that should be adopted by the management of the South Indian Bank Limited in selecting their subordinate staff and clerical staff for promotion to higher posts.

(d) Whether the number of posts of the Head Clerks in the administrative offices and in the branches of the South Indian Bank Limited, should be proportionate to the total number of clerical staff employed in the administrative offices and in the branches of the bank ? If so what should be such proportion and from what date ?

(e) Whether the South Indian Bank Employees Association is justified in demanding appointment of Audit Clerks to each Inspector in the services of the South Indian Bank Limited Trichur. If so, from what date such clerks should be appointed ?

(f) What should be the strength of Head Peons and Daftries in the Head Office and branches of the South Indian Bank Limited, Trichur and from what date. Whether the number of Head Peons and Daftries should be related to the total number of peons working in the Head Office and branches of the bank.

(g) Whether the South Indian Bank Employees Association is justified in demanding that the Peons in the branches of the Bank wherever cash collection of local cheques are involved should be designated as Bill Collectors ? If so from what date such peons should be redesignated as Bill Collectors ?

(h) Whether the South Indian Bank Employees Association is justified in demanding that when an employee is promoted to a higher post, the basic pay and allowances he would draw in the higher post should not be less than the basic pay and allowances he was drawing in the lower post and the difference, if any, should be absorbed in the basic pay itself.

2. The General Secretary of the South Indian Bank Employees Association, Trichur has filed a claim statement as follows : There was agitation and strike in May-August, 1973 when the management of the South Indian Bank (hereinafter referred to as the Bank) repudiated the terms of an earlier settlement with the union. The Union placed a charter of demands before the Management on 2-3-1974 regarding recruitment policy, method of appointment, promotion policy, fitment of promotion, categorisation of Head Clerks, Audit clerks, Head Peons, etc.

3. In respect of recruitment of subordinate staff, the Union demanded that the minimum qualification should be 5th standard and that the miximum qualification should be the completion of S.S.L.C. They demanded that S.S.L.C. passed candidates should not be entertained. The Union also contended that fresh appointments should be made from the relatives of the present employees who have put in 15 years of service. In respect of recruitment of officer cadre, the Union demanded that 80 per cent of the vacancies in the officer cadre should be filled by prormotion from among the clerical staff whose educational qualification is completion of S.S.L.C. The Union also demanded that there should be no direct recruitment in the officer cadre other than the technical posts like Chartered Accountants, Law Officers and Technical Officers. No trainee should be appointed in any cadres.

4. In respect of promotions, the Union demanded that all employees who have put in 7 years of service should be eligible for promotion after a written test. On promotion, their basic pay should increased by Rs. 100/- in the officer cadre and Rs. 25/- in the clerical cadre The Union then states that there should be a minimum of 50 Head clerks for the Bank and that there should be a ratio of 1:10 between the clerks and Head clerks The promotion of Head clerks should be strictly on the basis of seniority. The Union then demands that the Bank should appoint one Audit clerk to each Inspector. There should also be a Head Peon for five or more peons and the post of Daftries should also be created in all the branches The Peon doing the cash collection of the local cheques should be upgraded as Bill collectors. The Union then states in the claim statement that the Management is not at all coopeating with the Union in its demands and therefore all these demands should be complied with retrospective effect.

5. The Management of the South Indian Bank has filed a counter statements as follows : The demands of the Union are unreasonable and none of them can be complied with for the following reasons : The recruitment policy is purely a managerial function and the Union has nothing to do in the matter. The Bank is scrupulously following the

di ections given in the Awards and Bipartite settlements and the circulars of the Reserve Bank of India in the matter The Bank is entitled to engage trainees in the cadre of apprentices on daily wage or allowance basis and it does not violate any of the existing rules or laws. Regarding promotion, the Bank has already formulated a policy in pursuance of the agreements and Awards and there is no necessity to further discuss the matter with the Union. Regarding categorisation and fitment, the Bank has to follow the practice laid down in the Awards and Bipartite settlements and these matters will have to be discussed at an All India level. Further, the strength of the staff, their designation, distribution, etc., are all maters to be decided by the Management. The appointment of more Head Clerks, Audit Clerks Head Peons depends on the workload and it is the prerogative of the Management to decide and there cannot be a dispute with reference to these matters. No employee is drawing less than what he was drawing at the time of his promotion. Therefore, the demands of the Union on this aspect are all without substance.

6. The reference was made by the Government of India on 17-5-1975 and both parties had filed their respective statements in October, 1975. For some reason or other, the enquiry was adjourned from time to time and this Tribunal posted the matter for enquiry finally on 7-10-1976 by consent of both parties. On 7-10-1976, the parties were not ready and therefore on their request the enquiry was adjourned to 5-11-1976. Even on that date, the parties were not ready and both sides were informed by the Tribunal that the enquiry will positively go on at the next adjourned date on 15-11-1976 and it was adjourned peremptorily to that date. On 15-11-1976, the Union who is to begin the case was not ready with witnesses and therefore, at the request of the Union, the matter was again adjourned to 2-12-1976 finally. Thereafter, on an application, it was further adjourned to 24-12-1976 peremptorily. On 24-12-1976, the Management was ready, but the Union was not. The Union did not file any documents, though they have filed their claim statement as early as in October, 1975 nor summoned any witnesses. On 24-12-1976, learned counsel for the Union made a special request for a final adjournment and the Tribunal, as a matter of indulgence, adjourned the matter to 17-1-1977 with these observations : "Counsel for Union wants further adjournment. The request for adjournment is not at all justified. However, the Union is informed that if it does not get on with the case on the adjourned date, the enquiry will proceed even exparte, if necessary. Adjourned as a last chance by consent to 17-1-1977."

7. On 17-1-1977, the Management was ready with witness, but as usual, the Union was indifferent and not ready for enquiry. The Union had not taken any steps to summon or bring witnesses and, on the date of hearing, not a single employee or office bearer of the Union was present even to instruct the learned counsel for the Union The advocate for the Union requested a further adjournment and it was opposed by the learned counsel for the Management. There was not even a single soul for the Union to file an affidavit or a petition stating the grounds for further adjournment. Learned counsel orally asked for an adjournment, and since the request was not at all justified and since the parties were specially informed that the enquiry will go on 17-1-1977, the request for adjournment was rejected This is the oldest Industrial Dispute on the file of this Tribunal and it is twenty months old The union has throughout been indifferent and ignored the enquiry in spite of several adjournment from time to time The result is the Union was set exparte on 17-1-1977 and the enquiry proceeded. Learned counsel for the Union was present in the Court observing the enquiry, but he did not take part nor did he report 'no instructions' He did not also choose to cross-examine the witness on the side of the Management

8 It is clear from the reading of the issues found in the schedule for reference that the initial burden of proof in respect of many of the issues is on the Union which has made elaborate demands on behalf of the employees. As stated earlier, no witness was present on behalf of the Union and they have all avoided the witness box and kept themselves out The Management on its part examined M.W. 1 Thiru M P. Joseph who is now the Divisional Manager of South Indian Bank at Trichur He was the Chief Superintendent of Staff Department at Head Office Trichur till recently He has stated that the Management is strictly following the rules of the Bank and the provisions of the Bipartite settlement. According to him, the Bank has a policy for promotion and recruitment and that a subordinate staff is eligible for promotion, if he is an S. S. L. C. passed and also if he has further passed the written test held by the Bank. He then stated that the same system of promoion applies to officer's cadre also and that 25% of offirers posts are filled up by direct recruitment in the open market. This promotion system according to M. W. 1 was accepted by the Union in its Settlement dated 20-8-1973. He then stated that the Management invited the Union for a discussion for improving the present policy, but the Union never cared to come for discussion. M. W. 1 further stated that the Bank has not appointed any clerk on daily wage basis or stipends as alleged by the Union. The Bank normally appoints some trainees in the first instance and then absorb them if they are satisfactory. He then stated that there is no ratio between the clerks and the Head clerks in respect of appointment of Head clerks and that the claim of the Union for appointing Head clerks in the ratio 1 : 10 is untenable. There are only 21 Head clerks in the entire Management of the Bank which has 182 Branches all over the country.

9. The further evidence is that there is absolutely no need for employing Audit clerks to each Inspector nor any need for appointing more Head peons or Daftries. M. W. 1 is positive that there is no scope for adding to the present strength and that the posts of Head peons and Daftries in Branches are superfluous and wholly unnecessary. Daftries are only peons doing filing works, for which they are paid special allowances as per the Settlement. There is no need for formation of a separate category. Similarly, the witness says that peons are ordinarily employed for cash collections of cheques, for which they are paid special allowances. It is submitted that the Branches have only a very few cheques each day for collertion and that the Peon goes out and collects them, for which he is additionally remunerated. M. W. 1 says that most of the Branches in he mofussil do not require separate Cash Collector, since the work is very negligible. He then stated that an employee on promotion can never draw a lesser salary than what he was drawing at the time of promotion and that here is not even a single instanre of that kind throughout the hisory of this Bank. He finally stated that, in any event, the recruitment, promotion, transfers, etc., are all purely managerical functions which cannot be questioned. As stated already, learned counsel for the Union was present dhring the examination of this witness, but he did not choose to cross-examine perhaps due to want of instructions. Therefore the evidence of M. W. 1 stands uncontroverted. I have also persued the relevant Awards and I am satisfied that the Management has not violated any of the rules or provisions contained in the Awards or the Bipartite Settlements. In any event, the Union has not cared to substantiate to the Court as to which of the provision has been violated. They have also not shown to any extent that they are entitled to any of the reliefs asked for.

10 I have also applied my mind on the aspect whether the demands of the Union are fair and reasonable. But on the evidence I am of opion that the demands of the Union are wholly unjustified and untenable. They are a clear encroachment on the discretion of tre Management. For example there is nothing wrong in the Bank selecting a few apprentices now and then and give them training, so that they could be absorbed in future. The demand of the Union for increasing the posts of Head clerks is also not justified and the ratio of 1:10 cannot at all apply to the Branches of the Bank situated in the mofussil with a few clerks. Similarly, their demands for appointment of Audit clerks to each Inspector is also not necessary and this must be left to the discretion of the Management, which is governed by the rules of the Reserve Bank of India It is not for the Union to dictate to the Management to create new posts for their own advancement unless a very heavy workload is made out. Likewise, their demand for Head peon and Bill Collectors are extravagant and the Bank is not an Employment Agency providing or creating jobs for the unemployed. The result is that on merits the Union is not entitled to acceptance of any of the demands, since they are all unrelated to facts and practice In any event, the Union never raised its little finger during the course of the enquiry of twenty months to substantiate or prove any of the demands made by them,

11. The result is an Award is passed rejecting all the demands of the Union with costs. Advocate's fee Rs. 250 Dated, this 18th day of January, 1977.

T. N. SINGARAVELU, Presiding Officer

WITNESSES EXAMINED

For workmen.—None.

For management.—M.W.1—Thiru M. P. Joseph, Divisional Manager.

DOCUMENTS MARKED

For workmen.—Nil.

For Management.—Nil.

Note.—Parties are informed that they should take return of their documen's within six months from the date of the Award.

T. N. SINGARAVELU, Presiding Officer

[No. 12011/8/74-LR.III/D.III A]

S.O. 572.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the State Bank of India Region VI, New Delhi and their workman, which was received by the Central Government on the 28-1-77.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : DELHI.

CGID. No. 6 of 1976

BETWEEN

The State Bank of India, New Delhi.

AND

Its workman Smt. Indu Sharma—Cashier, as represented by Delhi Circle State Bank Staff Association.

PRESENT :

Shri Sachidanand Misra—for the management.

Shri J. K. Kapoor—for the workman.

AWARD

The Central Government on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L. 12012/148/75|D. II|A dated the 28th January, 1976 with the following terms of reference :—

"Whether the management of the State Bank of India, Region VI, Parliament House, New Delhi is justified in terminating the services of Smt. Indu Sharma, temporary Cashier, with effect from the 13th February, 1973. If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. The case of the workman, herein, relevant to the term of reference is that she was appointed as Cashier in the State Bank of India, Sadar Bazar, Delhi with effect from the 11th May, 1971 against a regular and permanent vacancy. She continued working as such regularly up to the 13th February, 1973 on which date her services were terminated all of a sudden without any cogent reasons with a view to adjust some other candidates in her vacancy. It was stated that the action of the bank in terminating her services was illegal and unjustified, as also, arbitrary, illegal, *malafide* and an act of unfair labour practice and victimisation. It was prayed that the bank be directed to pay her full wages ever since 14-2-73 and re-instate her with continuity of service.

3. The respondent, the State Bank of India, replied that the workman, herein, was appointed in a temporary capacity at various times and the last of the said appointments came to an end on the 13th February, 1973, and accordingly she ceased to be in the service of the bank. It was denied that her services were terminated with a view to adjust some other candidates. It was further stated that the pay in lieu of 14 days' notice was offered to the workman and that it was by virtue of the appointment being temporary that her services came to an end in terms of her appointment; hence it was prayed that the reference was liable to be rejected and the workman was not entitled to any relief.

4. On these pleadings the following issue was framed :—

ISSUE :

1. As in the terms of reference.

5. In oral evidence the management examined S/shri Khattu Ram-MW1, S. S. Kohli-MW2. In rebuttal came Smt. Indu Sharma-WW1, the workman concerned.

ISSUE NO.-1 (TERM OF REFERENCE) :

6. The main point for determination under the term of reference is whether the management of the State Bank of India was justified in terminating the services of Smt. Indu Sharma, temporary cashier—with effect from the 13th February, 1973.

7. The justifications which the management pleaded in this case were :

(a) that the services of the workman, herin, were temporary; and

(b) that they came to an automatic end.

8. The management, however, failed to substantiate these justifications. Giving evidence, its first witness Shri Khattu Ram-MW1 said in so many words that he did not known anything as to why the services of the workman, herein, were terminated. Shri S. S. Kohli-MW2 another witness for the management who was the branch manager and who terminated the services of Mrs. Indu Sharma said, "the services of Mrs. Sharma were terminated on 13-2-73, as they were no longer required. So far as he recollected, permanent hands had come by then." In cross-examination he said that the services of the workman came to an end on the date fixed in the letter of appointment.

9. In rebuttal Smt. Indu Sharma-WW1 said that there was no reason for terminating her services.

10. Considering this evidence, I am of the opinion that the management did not say that the services of the workman herein were terminated as they were temporary. What the witness Shri S. S. Kohli-MW2 said was that they were no longer required. However, reading both these things together on taking that both these things mean one and the same thing, temporary service, which can come to an end by itself means that either the job or the post is for a specified duration or that there is a temporary increase in work for which a temporay hand is requied. The management should have, therefore, proved that the job on which Mrs. Sharma was empfoyed was of a temporary nature, in that, the post itself was for a specified duration or the work of that post was for short duration or that there was temporary increase in work. The management, however, failed to show any of these things. The question of the services of Mrs. Sharma being no longer required, therefore, did not arise, as the management failed to show as to why her services were not required, that is to say, they were not required for the reason that the job at which Mrs. Sharma was employed finished or that the specified period for which the post was came to an end or that the temporary increase in work did not remain anymore. The management, thus, failed to prove that the services of Mrs. Sharma were terminated as they were temporary and were no longer required.

11. The truth, however, came out in the statement of Shri Kohli-MW2 who said, "permanent hands, had come by then", meaning thereby, that as the permanent hands came, Mrs. Sharma's services were no longer required and they were terminated. This mean, beyond doubt, that the post of cashier against which Mrs. Sharma worked was a permanent post and she worked on it pending selection of permanent hands. Her service was thus not temporary in the sense that her post was of a short duration or she worked against a post

which come into existence on account of a temporary increase in work.

12. The services of Mrs. Sharma were temporary only in the sense, that they were pending appointment of permanent hands. But, Mrs. Sharma was never told that her services would be terminated when the permanent hands arrived. There may have been some justification in dispensing with the services if she had been told so. Such a thing was not there nor was even pleaded. Hence, there was no justification.

13. For the justification that the services of Mrs. Sharma came to an automatic end, Shri Mishra urged that the Bank did not order a termination and the service came to an end by afflux of time; and no notice was needed.

14. The argument is devoid of any force in view of the latest decision of the Hon'ble Supreme Court in the case between State Bank of India and N. Sundramoney 1976 (32) FLR 197 in which it has been held that,

"Moreover, an employer terminates employment not merely by passing an order as the service runs. He can do so by writing a compositive order, one giving employment and the other ending or limiting it. A separate, subsequent determination is not the sole magnetic pull of the provision. A pre-emptive provision to terminate is struck by the same vice as the post-appointment termination. Dexterity of diction cannot defeat the articulated conscience of the provision."

15. Thus, there is nothing like an automatic termination. It is a termination made by the employer all the same and the services of Mrs. Sharma could not come to an end in the manner, sought to be done or automatically. She was entitled to a notice of at least 14 days in terms of her appointment letter and the law.

16. Hence, it is held that the termination of the services of the workman, herein, was not justified and the normal relief that she was entitled to get was re-instatement and full back wages.

17. Accordingly, the State Bank of India is directed to re-instate the workman on the post she held on 13-2-73 and pay her full back wages ever since till she is actually put back. She will be, also, treated in continuous services on her post. An award is made accordingly.

24th December, 1976. D. D. GUPTA, Presiding Officer

[F. No. 12012/148/75-D.II A]

R. P. NARULA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977

स्टाम्प

का० आ० 573.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धाराधारा (1) के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उस शुल्क से, जो तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा जारी किये जाने वाले साल करोड़ पन्द्रह लाख रुपये मूल्य के वचन-पत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य है, छूट देती है।

[सं० 1/77-स्टाम्प फा० सं० 33/11/77-विक्री-कर]

एस० डी० रामस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Banking)

(Revenue Wing)

ORDER

New Delhi, the 31st January, 1977

STAMPS

S.O. 573.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) the Central Government hereby remits the duty with which the promissory notes to the value of seven crores and fifteen lakhs of rupees, to be issued by the Tamil Nadu Electricity Board, are chargeable under the said Act.

[No. 1/77-Stamps/F. No. 33/14/77-ST]

S. D. RAMASWAMY, Under Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1977

का० आ० 574.—केन्द्रीय सरकार विकास परिषद (प्रक्रियात्मक) नियम, 1952 के नियम 3 और 8 के साथ पठित, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री के० हार्नले के स्थान पर प्रतिनिधि, भारतीय उर्वरक संगम और श्री एस० वेंकटारमण के स्थान पर श्री पी० जयन्त राव, ज्येष्ठ परियोजना अधिकारी को 5 अगस्त, 1977 तक की अवधि के लिए, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है अकार्बनिक रसायन उद्योग विकास परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं० का०आ० 2674/आई डी आर ए/6/4/75, तारीख 9 अगस्त, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

(1) क्रम सं० 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

"15 प्रतिनिधि
भारतीय उर्वरक संगम,
जवाहरलाल विश्वविद्यालय के निकट, नई दिल्ली।",

(2) क्रम सं० 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

"23 श्री पी० जयन्त राव,
ज्येष्ठ परियोजना अधिकारी,
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
नई दिल्ली।"

[आई०डी०आर०ए० 6/5/76 सं० 8/5/74—सी डी एन]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 3rd February, 1977

S.O. 574.— In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, read with rules 3 and 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints, representative of the Fertilizer Assoc-

611

Hartley and Shri P Jayantha ice Shri S. Venketaraman, as Council for Inorganic Chemi- pto and inclusive the 5th August, owing amendment in the Order of in the Ministry of Industry; Depart- evelopment No. S. O. 2674-IDRA/6/ August, 1975, namely :—

Order, in paragraph 1

serial No. 15 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely : -

"15. Representative,
Fertilizer Association of India, Near Jawahar Lal Nehru University, New Delhi."

(ii) for serial No. 23 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :- -

"23 Shri P. Jayantha Rao,
Senior Project Officer,
Ministry of Chemical and Fertilizer,
New Delhi."

[IDRA '6/5/76/No. 8/5/74-CDN]
PREM NARAIN, Under Secy

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1977

का० आ० 575.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मास्टर योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है जिसे सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपनी आपत्ति या सुझाव इस जापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दे। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें वे अपना नाम एवं पूरा पता भी लिखें।

संशोधन

1.1 हैक्टर (2.7 एकड़) का क्षेत्र जो जोन डी-5 (डी आई जैड क्षेत्र) में पड़ता है, जो पूर्व में 30.5 मी० (100') मंदिर मार्ग के मार्गाधिकार, उत्तर में मन्दिर लेन, पश्चिम में नाला तथा दक्षिण में 61 मी० (200') चौड़ी शंकर रोड, मन्दि मार्ग के साथ साथ (काली बाड़ी तथा शंकर रोड) द्वारा घिरा हुआ है। मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में यह "मनोरंजन हेतु निर्दिष्ट है, इसे अब सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं (संस्थानीय धार्मिक)" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।

शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली-1 में उक्त अवधि में आकर प्रस्तावित संशोधन के मानचित्र का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं० एफ० 16(146)/75-एम० पी०]

हृदय नाथ फोतेदार, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th February, 1977

S.O. 575.—The following modification, which the Central Govt. proposes to make the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

The land use of an area, measuring 1.1 hectares (2.7 acres) in zone D-5 (D. I. Z. Area), bounded by Mandir Marg 30.5 mts. (100 ft.) right-of-way in the east, Mandir Lane in the north, nallah in the west and 61 mts. (200 ft.) wide Shankar Road in the south, along Mandir Marg (between Kali Bari and Shankar Road) earmarked as "recreational" in the Master Plan/Zonal Development Plan, is proposed to be changed to "public & semi-public facilities (institutional-religious)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, 11th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 16(146)/75-M.P.]

H. N. FOTEDAR Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1977